सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

परिवहन विशेष

www.newsparivahan.com

वर्ष 02, अंक 84, नई दिल्ली । बुधवार, 05 जून 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं होता और विनम्रता से बढ़कर कोई व्यवहार नहीं होता।

03 दिल्ली में फिर नहीं खुला किसी तीसरे दल का खाता
06 कौन भुगतेगा चुनावी गारंटी का खामियाजा
08 आइए हम सब मिलकर अपने आस - पास छायादार पेड़ लगाएं

'तीसरा कार्यकाल देश के बड़े फैसलों के लिए समर्पित, ये मोदी की गारंटी', नतीजों के बाद बोले पीएम मोदी

संजय बाटला

लोकसभा चुनाव के नतीजों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा मुख्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने देश को संबोधित किया। मंच से उन्होंने महिलाओं सहित सभी मतदाताओं के प्रति आभार जताया।

नई दिल्ली। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव में जनता ने एक बार फिर चौंका दिया। लोकसभा चुनाव में आए जनादेश ने सारे अनुमानों को ध्वस्त कर दिया। भाजपा बहुमत का आंकड़ा तक नहीं छू पा रही है। दो बार अपने दम पर सरकार बनाने वाली भाजपा इस बार गठबंधन की मदद से सरकार बना पाएगी। मतगणना के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा मुख्यालय पहुंचे।

यहां उन्होंने अपना संबोधन जय जगन्नाथ के नाम से शुरू किया। उन्होंने कहा कि जनता जनार्दन के हम सभी ऋणी हैं। जनता ने भाजपा पर एनडीए पर पूर्ण विश्वास जताया है। आज की यह विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। यह भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। ये विकसित भारत के प्रण की जीत है। ये सबका साथ, सबका विकास की जीत है। यह इस मंत्र की जीत है। यह 140 करोड़ भारतीयों की जीत है।

उन्होंने आगे कहा कि मैं आज देश के चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करुंगा। चुनाव आयोग ने दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव इतनी कुशलता के साथ संपन्न कराया है। इस चुनाव में करीब 100 करोड़ मतदाता, 11 लाख पोलिंग स्टेशन, 55 लाख वोटिंग मशीन, 1.5 करोड़ मतदान कर्मियों ने साथ काम किया। भारत की चुनाव प्रक्रिया, चुनाव के पूरे सिस्टम पर हर भारतीय को गर्व है। ये अपने आप में बहुत बड़ा गौरव का विषय है।

ओडिशा में पहली बार बनेगी भाजपा सरकार

इस बार चुनाव में कुछ और चीजें देखने को मिलीं। अरुणाचल हो या सिक्किम, आंध्र प्रदेश हो या ओडिशा, कांग्रेस को जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया। ओडिशा में भाजपा सरकार बनाने जा रही है। लोकसभा चुनाव में भी ओडिशा ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। यह पहली बार होगा जब महाप्रभु जगन्नाथ की जमीन पर भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। पीढ़ियों

से जिस क्षण का इंतजार किया, वह आज सफलता को चूमने लगी है।

हमने कई राज्यों में क्लीन स्वीप किया

तेलंगाना में हमारी संख्या दोगुना हो गई है। मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल और ऐसे कई राज्यों में हमारी पार्टी ने लगभग क्लीन स्वीप किया है। मैं इन सभी राज्यों और अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम विधानसभा के मतदाताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं इन राज्यों की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र सरकार आपके विकास के लिए कोई कोर-कसर बाकी नहीं छोड़ेगी।

सहयोगी दलों का मंच से लिया नाम

पीएम मोदी ने कहा कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया। बिहार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया। दोस्तों 10 साल पहले देश ने हमें जनादेश दिया था। 2013-14 में देश एक निराशा की गर्त में डूब चुका था। हर दिन अखबारों की हेडलाइन ऐसी ही होती थीं। ऐसे समय में देश ने हमें निराशा के गहरे सागर से आशा के मोती निकालने का जिम्मा सौंपा था।

आत्म निर्भर बनाने के लिए करेंगे काम

पीएम मोदी ने मंच से कहा कि देश के इतिहास में महिलाओं द्वारा दिए गए वोटों से रिकॉर्ड टूट गया है। मैं इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता। देश की कोटि-कोटि माताओं-बहनों ने मुझे नई प्रेरणा दी है। राष्ट्र प्रथम की भावना हमें लक्ष्य हासिल करने का हौसला देती है। हमने दुनिया की सबसे बड़ी जनकल्याणकारी योजनाएं चलाईं। आजादी के 70 साल बाद 12 करोड़ लोगों को नल से जल मिला है। आजादी के 70 साल बाद चार करोड़ जनधन खाते खुले हैं। अनुच्छेद 370 हटा, बैंकिंग रिफॉर्म हुए, जीएसटी आई। आप याद करिए कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, हमने हर दबाव से हटकर कदम उठाया और इसी का नतीजा है कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती बड़ी इकोनॉमी है। राष्ट्र प्रथम की यही भावना भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी। साथियों हमारे सामने एक महान संकल्प है। विकसित भारत का संकल्प। 10 साल के बाद लगातार तीसरी बार जनता-जनार्दन का प्यार, उनका आशीर्वाद हमारा हौसला बढ़ाता है। हमारे संकल्प को नई मजबूती, ऊर्जा देता है। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए, जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेले भाजपा ने जीती हैं।

आप एक कदम चलेंगे, मोदी चार कदम चलेगा

उन्होंने कहा कि देश के कोने-कोने में उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं से मैं कहूंगा कि आपकी मेहनत इतनी गर्मी में आपका बहाया पसीना ये मोदी को निरंतर काम करने की प्रेरणा देता है। मैं देशवासियों से दोबारा दोहराना चाहता हूं कि 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 18 घंटे काम करेगा। आप एक कदम चलेंगे, मोदी चार कदम चलेगा। तीसरे कार्यकाल में देश बडे.फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। ये मोदी की गारंटी है।

पंजाब के खिलचियां में एचआरटीसी की चलती बस में लगी आग, देखते ही देखते...

एचआरटीसी की एक चलती बस में अचानक लग गई। घटना पेश आई पंजाब के खिलचियां स्टेशन के समीप। वहीं, बस में ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा 14 यात्री सवार थे।

हिमाचल पथ परिवहन निगम डिपो हमीरपुर की हमीरपुर से अमृतसर रूट पर जा रही बस में अचानक आग लग गई। यह घटना पंजाब के खिलचियां स्टेशन के समीप पेश आई है। अभी तक आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। निगम के हमीरपुर डिपो के अधिकारी सूचना मिलने के बाद ही मौके के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान बस में चालक और परिचालक के अलावा 14 यात्री सवार थे। सभी यात्री, चालक और परिचालक बड़ा हादसा होने से बाल-बाल बच गए हैं। हमीरपुर डिपो की बस हमीरपुर बस अड्डा से सुबह 10:30 बजे रवाना हुई। बस शाम सवा पांच बजे के करीब व्यास व अमृतसर के बीच स्थित खिलचियां स्टेशन के पास पहुंची तो बस में अचानक अंगारियां उठने लगी। ऐसे में बस ड्राइवर ने तुरंत बस को ब्रेक लगाई और यात्रियों को बस से जल्दी नीचे उतारा। यात्री और बस ड्राइवर-कंडक्टर जैसे ही नीचे उतरे, तो बस से आग की तेज लपटें उठने लगी और देखते ही देखते बस आग से राख हो गई। बस में आग कैसे लगी इसकी सही जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि बढ़ता तापमान भी इसकी एक वजह बताया जा रहा है। वहीं, निगम के उपमंडलीय प्रबंधक राजकुमार पाठक का कहना है कि हमीरपुर से अमृतसर रूट पर जा रही हमीरपुर डिपो की बस में पंजाब में चलती बस में अचानक आग लग गई। बस में बैठे यात्री व ड्राइवर-कंडक्टर सभी सुरक्षित हैं।

चारधाम यात्रा 2024: मानसूनी सीजन में यात्रा मार्ग पर रहता है खतरा, वाहन संचालकों के लिए निर्देश जारी

जारी निर्देशों में कहा गया कि यात्राकाल में बारिश में भूस्खलन और बादल फटने का खतरे के मद्देनजर सभी वाहन चालक मौसम साफ होने का इंतजार करें।

परिवहन विशेष न्यूज

देहरादून। मानसूनी सीजन में चारधाम यात्रा को लेकर नोडल अफसर सुनील शर्मा ने सुरक्षित संचालन के निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत सभी चालकों को सतर्क किया गया है। उन्हें बताया गया कि यात्राकाल में उन्हें क्या सावधानियां बरतनी हैं।

जारी निर्देशों में कहा गया कि यात्राकाल में बारिश में भूस्खलन और बादल फटने का खतरे के मद्देनजर सभी वाहन चालक मौसम साफ होने का इंतजार करें। ये सुनिश्चित कर लें कि वाहन के महत्वपूर्ण यंत्र जैसे हेडलाइट, टेल लाइट, डिपर और वाइपर ठीक से काम कर रहे हों। बारिश में पर्वतीय मार्गों पर धीमी गति से वाहन चलाएं क्योंकि ब्रेक सिस्टम स्लो काम करताा है।

बारिश में पर्वतीय मार्गों पर वाहन चलाते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि वाहन की हेडलाइट ऑन हो और आगे-पीछे के शीशे के वाइपर चलते हुए हों। वाहन चालक अन्य वाहनों से सुरक्षित दूरी पर वाहन का संचालन करें, ताकि इमरजेंसी ब्रेक मारने पर हादसा न हो। उन्होंने कहा, सड़क पर भरे हुए पानी से वाहन न निकालें।

कहा, कई बार पानी के कारण टायर सड़क की सतह से पकड़ खो देते हैं, जिससे हादसा हो सकता है। उन्होंने वाहनों को हवादार रखने को भी कहा, ताकि शीशों को धुंध से बचाया जा सके। सभी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों को इन निर्देशों का पालन कराने को कहा गया है।

वृंदावन जा रहे यात्रियों की दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस-वे पर डिवाइडर से टकराई बस, 20 घायल...

दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस-वे पर भोजपुर थाना क्षेत्र में अनियंत्रित बस डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में बस में सवार 20 यात्री घायल हो गए। सभी महाराष्ट्र के नासिक के रहने वाले हैं। 13 मई को चार धाम की यात्रा पर निकले थे। केदारनाथ के बाद हरिद्वार गए थे। सोमवार रात को हरिद्वार से वृंदावन के लिए निकले।

मोदीनगर। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस-वे पर भोजपुर थाना क्षेत्र में अनियंत्रित बस डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में बस में सवार 20 यात्री घायल हो गए। सभी महाराष्ट्र के नासिक के रहने वाले हैं। 13 मई को चार धाम की यात्रा पर निकले थे। केदारनाथ के बाद हरिद्वार गए थे।

सोमवार रात को हरिद्वार से वृंदावन के लिए निकले। रास्ते में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर बस डिवाइडर से टकराई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को मोदीनगर सीएचसी में भर्ती कराया। कई यात्रियों को फ्रेक्चर है। सभी नासिक के शिरडी व अमन नगर के रहने वाले हैं।

पर्यावरण दिवस विशेष: जमीनी स्तर पर गंभीर कार्रवाई की आवश्यकता : अंकुर

हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जो हमें पर्यावरण के संरक्षण और सुरक्षा की दिशा में गंभीरता से सोचने और काम करने का मौका देता है। यह केवल एक दिन नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के हर दिन हमें पर्यावरण को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, यह महत्वपूर्ण है कि हम किसी राजनीतिक दल या प्रणाली को दोष दिए बिना, अपने व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाएं।

नागरिकों की भूमिका

भारत के नागरिक होने के नाते, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने पर्यावरण को साफ-सुथरा रखें और एक सतत जीवन शैली अपनाएं। हमारे छोटे-छोटे कदम मिलकर बड़े बदलाव ला सकते हैं। हमें समझना होगा कि पृथ्वी हमारी माता है और उसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है।

क्या कर सकते हैं हम ?

कचरा प्रबंधन: हमें अपने घरों और आसपास के क्षेत्रों में कचरा फैलाने से बचना चाहिए। कचरे को अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित करके पुनर्चक्रण (रिसाइकलिंग) के लिए भेजना चाहिए।

प्लास्टिक का उपयोग कम करें: प्लास्टिक पर्यावरण के लिए अत्यधिक हानिकारक है। हमें सिंगल-यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करना चाहिए और इसके स्थान पर पुनः उपयोग होने वाले बैग, बोतलें और बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए।

जल संरक्षण: जल हमारी सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। हमें पानी की बर्बादी रोकनी चाहिए और पानी के उपयोग में सतर्कता बरतनी चाहिए। वर्षा जल संचयन (रेनवाटर हार्वेस्टिंग) को अपनाना चाहिए।

ऊर्जा बचत: बिजली और ईंधन के अत्यधिक उपयोग से बचें। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करें।

वृक्षारोपण: अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और उनकी देखभाल करें। पेड़ न केवल पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं बल्कि हमें शुद्ध हवा और छाया भी प्रदान करते हैं।

परिवहन: सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, साइकिल चलाएं या पैदल चलें। यह न केवल पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है।

शिक्षा और जागरूकता

पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता और शिक्षा महत्वपूर्ण है। हमें अपने बच्चों और युवाओं को पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में बताना चाहिए और उन्हें प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए।

पर्यावरण संरक्षण एक सामूहिक प्रयास है और इसमें हम सभी की भागीदारी आवश्यक है। आइए इस पर्यावरण दिवस पर संकल्प लें कि हम व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर ऐसे कदम उठाएंगे जो हमारे पर्यावरण को सुरक्षित और स्वस्थ बनाए रखेंगे। हमारे छोटे-छोटे प्रयास मिलकर एक बड़े बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं।

हमारा पर्यावरण, हमारी जिम्मेदारी!

indiangreenbuddy@gmail.com

खुशहाल जिंदगी की है चाहत? आज से सीख लें इन 10 चीजों को 'ना' कहना, दूर रहेंगी बेमतलब की परेशानियां

आज के व्यस्त जिंदगी में खुशियां ढूंडना आसान काम नहीं. लोगों को दायरा सिमट रहा है और सोशल मीडिया पर लोगों का भरोसा बढ़ता जा रहा है. ऐसे में दुनिया मायावी लगती है. अधिकांश लोग खुश नहीं हैं और खुश दिखने की कोशिश कर रहे हैं.

दरअसल, हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां प्राथमिकता अपनी खुशी या सुकून का नहीं, बल्कि चैलेंज और प्रतियोगिताओं को दी जा रही है. ऐसे में हमारा सारा ध्यान अपनी खुशियों से अधिक 'कुछ और' होता जा रहा है. आपको बता दें कि अगर आपको अंदर से खुद को खुश रखना है तो सबसे पहले 'ना' कहने की क्षमता बढ़ाएं. उन चीजों को 'ना' कहना सीख लें, जिन्हें पूरा करने में आपकी सारी एनर्जी चली जाती है लेकिन फिर भी सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता . अगर आप अपनी खुशियों और खुद को प्राथमिकता देने के लिए कुछ चीजों को 'ना' कहना सीख लें तो यकीन मानिए, आपसे खुशहाल कोई नहीं होगा. आइए जानते हैं कि जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए किन चीजों को 'ना' करना सीखना बहुत जरूरी है.

खुश रहना है तो इन 10 चीजों को 'ना' कहना सीख लें-

1-अगर आपके लाइफ में ऐसे दोस्त, रिश्तेदार या पार्टनर हैं जो केवल आपमें कमी निकालते रहते हैं और नेगेटिव फीडबैक देते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहकर आप ड्रेन आउट हो सकती हैं. ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप को ना कहें.

2-अगर आपसे लोग या आप खुद ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखती हैं तो यह आपको कभी भी खुश नहीं होने देंगी. इसलिए जिंदगी में रियलिस्टिक गोल तय करें और बेकार के एक्सपेक्टेशन को ना कहें.

3-अगर कोई आपकी तुलना किसी और से करता है तो ऐसी चीजों को सिरे से ना कहना जरूरी है. अपनी तुलना कभी भी किसी से ना करें और अपनी यूनीक क्वालिटी और ताकत को पहचानें.

4-अगर आप अपने बारे में केवल निगेटिव सोचती हैं तो ऐसी सोच से बचें. बेहतर होगा कि आइने के सामने खड़े होकर खुद से अच्छी बातें करें और मुस्कुराएं.

5-ओवर कमिटमेंट को ना कहें. आज के जमाने में लोग ओवर कमिटमेंट के जाल में फंस जाते हैं और उम्मीदों को पूरा करते करते जिंदगी गुजार देते हैं. ऐसे हालातों से बचें.

6-डर को ना कहें. अगर हर वक्त किसी रिश्ते या किसी चीज के खोने का डर मन में बना रहता है तो आप कभी भी नई उड़ान नहीं भर पाएंगी. इसलिए कुछ खोने के डर को ना कहें.

7-लोगों को खुश करना एक ऐसा जाल है जिसमें अधिकतर लोग फंस जाते हैं और खुद की खुशियों को अनदेखा कर आगे बढ़ते जाते हैं. यह आपके मेंटल सेहत के लिए खतरनाक है. इससे ना कहें.

8-किसी काम को टालते जाना एक बुरी आदत है और यह आपके लिए मुसीबत खड़ा कर सकती है. इसलिए बेहतर होगा कि आप चीजों को टालने से बचें और ऐसे हालात को ना कहें.

9-ऐसी आदतें जिसकी वजह से आपकी सेहत दांव पर लग रही है मसलन, खराब डाइट, व्यायाम आदि ना करना, मेंटल सेहत के साथ खिलवाड़ आदि को ना कहें.

10-खो जाने का डर, जी हां, कई लोग हैं जो इसलिए लोगों को खुश करने में लगे हुए हैं कि कहीं वे भीड़ में अकेला ना हो जाएं. यह डर आपको हर वक्त एंग्जायटी में रख सकता है और आपकी खुशियां छीन सकता है. इसलिए ऐसे डर को निकालें और खुद पर भरोसा रखें.

सिर्फ प्रेग्नेंसी नहीं, इन कारणों से भी पीरियड्स में हो सकती है देरी, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया डिले होने की अन्य 8 वजहें

अगर पीरियड शुरू होने में देरी हो रही है तो इसका मतलब यह कतई नहीं कि आप प्रेग्नेंट ही हैं . प्रेग्नेंसी के अलावा भी कई वजहें हैं जिसके कारण पीरियड्स में देरी हो सकती है . आइए जानते हैं इन वजहों को .

ज्यादातर महिलाओं में यह मिथ है कि पीरियड अगर समय पर शुरू नहीं हुआ तो इसकी वजह प्रेग्नेंसी होती है. ऐसे में जब पीरियड्स शुरू हो जाता है तो वे इसकी वजहों के लिए बेफिक्र हो जाती हैं. आपको बता दें कि महिलाएं अगर अपनी सेहत को लेकर कॉन्शस हैं तो उन्हें यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर पीरियड्स में देरी की वजह क्या क्या होती हैं.

जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट रिद्धिमा बत्रा ने बताया कि दरअसल पीरियड्स कई वजहों से डिले या मिस हो सकता है. यह हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से डिले हो सकता है. यही नहीं, कई बार तो कुछ डिजीज की वजह से पीरियड मिस भी हो सकता है.

पीरियड्स अगर मिस हो गया या डिले हो रहा है तो इसकी एक वजह एकाएक वजन का बढ़ना या एकाएक तेजी से वजन का घटना हो सकता है. ऐसे हालात में अक्सर पीरियड ईरेग्युलर होने लगता है.

अगर महिला कई दिनों में बहुत अधिक तनाव झेल रही हैं या किसी बात की चिंता सता रही है तो इसकी वजह से शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलाव होने लगते हैं जिसका असर पीरियड्स पर भी पड़ता है.

कई महिलाएं बेहतर सेहत के लिए या फिटनेस बढ़ाने के लिए हेवी वर्कआउट करती हैं. इसकी वजह से भी पीरियड्स के डेट में बदलाव हो सकता है. एथलीट्स में ऐसी समस्या काफी कॉमन हैं.

अगर आपका थायराइड ग्लैंड अच्छी तरह काम नहीं कर रहा और कम या ज्यादा हार्मोन्स रिलीज कर रहा है तो यह पीरियड मिस होने या पीरियड्स में डिले की वजह बन जाता है. ऐसा होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. कई बार इसकी वजह से महीनों पीरियड्स रुक सकता है जिसे एमेनोरिया भी कहते हैं.

इसके अलावा, अगर शरीर में न्यूट्रिशन की कमी है, आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं तो भी पीरियड साइकिल में बदलाव आ सकता है. साथ ही, मेनोपॉज, हार्मोनल बदलाव भी इसकी बड़ी वजह हो सकता है।

प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में 20% महिलाओं में दिखते हैं गंभीर लक्षण, डेली लाइफ होती है बाधित, 5 पोषक तत्व पीएमएस को करेंगे कम

प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम को कम करने के लिए ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर फूड्स खाएं.प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम को कम करने के लिए ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर फूड्स खाएं. प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम महिलाएं अपने मासिक धर्म से पहले के हफ्तों में अनुभव कर सकती हैं. पीएमएस या प्रीमेंस्ट्रुअल

महिलाओं को हर महीने पीरियड्स आना एक नेचुरल प्रॉसेस है, लेकिन इसके साथ कई तरह की शारीरिक तकलीफें भी झेलनी पड़ती हैं. मासिक धर्म के पहले दो दिन तो अधिकतर महिलाएं पेट, कमर, जांघों, सिर दर्द से गुजरती हैं, लेकिन पीरियड्स आने से कुछ दिनों पहले भी कई तरह की शारीरिक समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं. समझ लीजिए कि ये तकलीफ, दर्द इस बात का इशारा करती हैं कि अब आपको कुछ दिनों में पीरियड्स आ सकते हैं. इसे प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम (premenstrual syndrome) कहते हैं. इसमें कई लक्षण तो ऐसे होते हैं जो डेली रूटीन लाइफ को भी बाधित कर देती हैं. यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो इसे आप कुछ खास पोषक तत्वों को अपनी डाइट में शामिल करके प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम (PMS) के लक्षणों को कम कर सकती हैं.

क्या है प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम?

पीएमएस या प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम उन लक्षणों का नाम है जो महिलाएं अपने मासिक धर्म से पहले के हफ्तों में अनुभव कर सकती हैं. अधिकांश महिलाओं को कभी न कभी पीएमएस होता है. न्यूट्रिशनिस्ट लवनीत बत्रा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के बारे में एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वे लिखती हैं कि प्रजनन आयु (reproductive age) की लगभग 48% महिलाओं को पीएमएस का अनुभव होता है. साथ ही इनमें से लगभग 20 प्रतिशत महिलाओं के लिए प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के लक्षण इतने गंभीर होते हैं कि उनकी दिनचर्या तक बाधित हो जाती है.

प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम को कम करने वाले पोषक तत्व

यहां बताए गए 5 पोषक तत्वों को आप अपनी डाइट में जरूर शामिल करें. इससे काफी हद तक आपको पीएमएस (PMS) को कम करने में मदद होगी.

1. कैल्शियम: अक्सर पीरियड्स शुरू होने से पहले कुछ महिलाओं में काफी मूड स्विंग, ऐंठन और वॉटर रिटेंशन की समस्या होती है. इसके लिए आप कैल्शियम से भरपूर चीजों का सेवन करें, लाभ होगा. रागी, दही, तिल के बीज खाएं.

2. मैग्नीशियम: प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के लक्षणों में ब्रेस्ट में दर्द, टेंडर्नेस, ब्लोटिंग, मूड स्विंग आदि भी शामिल हैं. इन्हें कम करने के लिए आप मैग्नीशियम से भरपूर फूड्स का सेवन करें. बादाम, काजू, कद्दू के बीज मैग्नीशियम के बेस्ट सोर्स हैं.

3. विटामिन बी6: कई बार कुछ महिलाओं में स्ट्रेस, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, ब्रेस्ट टेंडर्नेस की समस्या पीरियड्स की डेट आने से 10 दिनों पहले से शुरू हो जाती है. इसके लिए आप विटामिन बी6 युक्त चीजों का सेवन करें. खरबूजा, पपीता, सफेद जिसे हम छोले या काबूली चना भी कहते हैं डाइट में शामिल करें.

4. ओमेगा-3 फैटी एसिड: ब्लोटिंग और मूड स्विंग को कम करने में मदद कर सकते हैं ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर फूड्स. घी, सैल्मन मछली, अलसी के बीज खा सकती हैं.

5. विटामिन डी: थकान और मूड स्विंग को कम करने में मदद करता है विटामिन डी युक्त फूड्स. इन सभी चीजों को आप पीरियड्स की डेट आने से 15 दिन पहले खाना शुरू कर दें. प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के लक्षणों को कम करना काफी आसान होगा और इन दिनों काफी आराम भी मिलेगा. सुबह की हल्की धूप में बैठें. फोर्टिफाइड फूड्स, सैल्मन मछली खाएं।

बोर्ड रिजल्ट में स्कूल की टॉपर रही बेटी? आगे की पढ़ाई विदेश में, एजुकेशन लोन लेकर सफर करें आसान, जानें सबकुछ

अपनी बेटी को विदेश पढ़ने भेजना चाहते हैं तो इसके लिए खर्च की चिंता करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि कई बैंक हैं जो विदेश में शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन देते हैं. आइए जानें कौन से बैंक हैं जो एजुकेशन लोन दे रहे हैं और क्या ब्याज दरें हैं इनकी...

एक के बाद एक राज्यों से 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम आ रहे हैं. हर साल की तरह इस बार भी बेटियां बाजी मार रही हैं. क्या आप अपनी बेटी को विदेश पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं? या फिर बेटी 12 वीं क्लास में आई है और अगले साल के लिए आप विदेश में एजुकेशन को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं? दोनों में से कोई भी परिस्थिति हो, आपकी बेटी की आगे की पढ़ाई विदेश के किसी बेहतरीन संस्थान में हो, इसके लिए आपको विभिन्न शैक्षणिक कोशिशों के अलावा खर्च मैनेज करने का तनाव भी होगा. आइए आज जानते हैं भारत में मौजूद ऐसे एजुकेशन लोन के बारे में जो फॉरेन में पढ़ाई और प्रवास के दौरान के विभिन्न खर्चों को हैंडल करते हैं.

कम ब्याज दरों पर एजुकेशन देने वाले बैंकों की इस कैटिगरी में कई योजनाएं हैं जिन्हें अपनी जरूरत के मुताबिक चुन सकते हैं. विदेशी होम लोन के अंतर्गत आने वाले खर्चों में ट्यूशन फीस, रहने का खर्च और अन्य कई खर्चों जैसे लैपटॉप या किताबों की खरीददारी, फ्लाइट टिकट जैसे जरूरी खर्चें शामिल हैं. फॉरेन एजुकेशन लोन के लिए वित्तीय संस्थान को शॉर्टलिस्ट करते समय, स्टूडेंट्स और उनके पैरेंट्स को कई जरूरी फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए. जैसे कि कौन सा बैंक क्या ब्याज दर दे रहा है, लोन रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग की फीस और इसमें लगने वाला समय, लोन टेन्योर, प्रीपेमेंट की शर्तें आदि. (बेटी पैदा हुई है? डॉक्टर बनाना है बिटिया को तो आज से ही शुरु कर दें तैयारी, स्टेप-बाई-स्टेप गाइड)

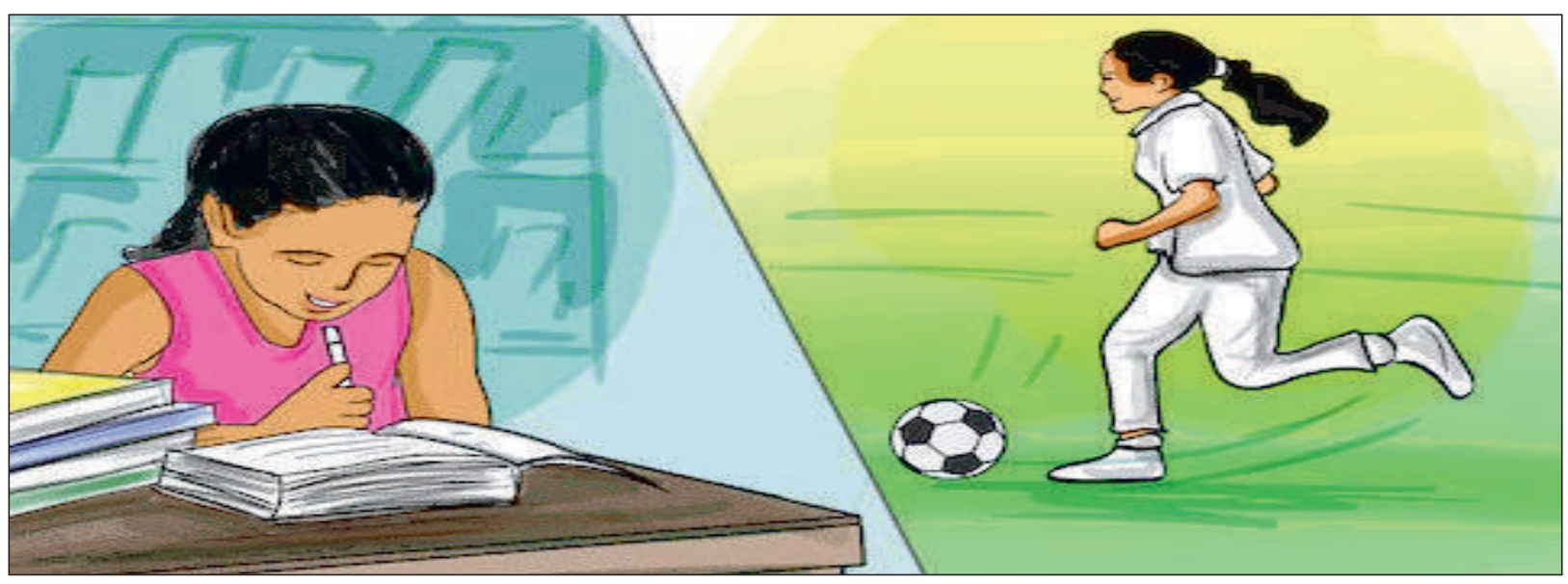

बैंक बाजार डॉट कॉम के डाटा के मुताबिक, टॉप 10 बैंक जो सात साल की अवधि के साथ 50 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन 13.7 प्रतिशत से कम ब्याज दर के साथ देते हैं, वे ये हैं. यहां ध्यान दें कि न्यूज18 हिन्दी डिजिटल पर यह लेख केवल प्राथमिक जानकारी के लिए लिखा गया है. आप अपनी जरूरतों और क्षमता के मुताबिक आखिरी फैसला लें. सुकन्या समृद्धि स्कीम के बारे में सारी जानकारी आप यहां क्लिक करके ले सकते हैं.

भारतीय स्टेट बैंक फॉरेन एजुकेशन लोन पर लगाया जाने वाला ब्याज 11.15 प्रतिशत से शुरू होता है. यह कई दूसरे बैंकों से थोड़ी ज्यादा है. सात साल की अवधि के लिए 50 लाख रुपये के लोन के लिए ईएमआई 86,007 रुपये होगी.

एचडीएफसी बैंक 12.50 प्रतिशत की ब्याज दर से शुरू होने वाला फॉरेन एजुकेशन लोन देता है. सात साल की अवधि वाले 50 लाख रुपये के ऋण पर ईएमआई 89,606 रुपये होगी.

इंडियन बैंक में फॉरेन एजुकेशन लोन पर 8.6 प्रतिशत से शुरू होने वाली ब्याज दरें हैं. सात साल की अवधि के लिए 50 लाख रुपये के विदेशी शिक्षा ऋण पर ईएमआई 79,435 रुपये बनती है.

एक्सिस बैंक 13.7 प्रतिशत की ब्याज दर से शुरू होने वाले फॉरेन एजुकेशन लोन प्रदान करता है जिसकी सात साल की अवधि के लिए 50 लाख रुपये के लोन पर ईएमआई 92,873 रुपये होगी.

बैंक ऑफ इंडिया विदेशी शिक्षा ऋण पर 11.85 प्रतिशत से शुरू होने वाली ब्याज दरों की पेशकश करता है। सात साल की अवधि वाले 50 लाख रुपये के ऐसे ऋण पर ईएमआई 87,863 रुपये होगी

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विदेशी शिक्षा ऋण पर 9.25 प्रतिशत से शुरू ब्याज लेता है. सात साल की अवधि के लिए 50 लाख रुपये के विदेशी शिक्षा ऋण पर ईएमआई 81,081 रुपये होगी.

(महिलाओं और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए आप यहां क्लिक कर सकती हैं)

बैंक ऑफ बड़ौदा फॉरेन एजुकेशन लोन पर 9.7 प्रतिशत से शुरू होने वाली ब्याज दरों की पेशकश करता है. इसमें सात साल की अवधि के लिए 50 लाख रुपये के ऋण पर ईएमआई 82,233 रुपये होगी.

आईसीआईसीआई बैंक और पंजाब नेशनल बैंक दोनों ही बैंक फॉरेन एजुकेशन लोन पर 10.25 प्रतिशत से शुरू होने वाली ब्याज दरें लेते हैं. सात साल की अवधि के लिए 50 लाख रुपये के ऐसे ऋण पर ईएमआई 83,653 रुपये होगी. (गोल्ड लोन है कमाल की चीज! लेकिन नहीं चुकाया तो खो बैठेंगी नानी-दादी के कंगन, हो सकती है नीलामी)

केनरा बैंक फॉरेन एजुकेशन लोन पर 10.85 प्रतिशत से शुरू होने वाली ब्याज दरों की पेशकश करता है. सात साल की अवधि के लिए 50 लाख रुपये के ऋण पर ईएमआई 85,218 रुपये होगी।

तस्वीरों में दिल्ली का माहौल: भाजपा मुख्यालय में जीत के शंखनाद की गूंज, कांग्रेस में जश्न, आप में छाया सन्नाटा

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के रुझान और नतीजे आने के बाद डीडीयू मार्ग स्थित भाजपा मुख्यालय में शंखनाद शुरू हो गया। 'भारत माता की जय' और 'मोदी है तो मुमकिन है' जैसे नारों गूंज सुनने को मिली। रुझानों में बढ़त देख भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ता गया। कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते-थिरकते दिखे। दोपहर 12 बजे के करीब जब जीत स्पष्ट होने लगी तो वैसे ही कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर एक-दूसरे का मुंह मीठा किया। जश्न को लेकर सुबह से ही कार्यकर्ता अलग-अलग अंदाज में यहां पहुंचते नजर आए। कोई साइकिल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटआउट, तो कोई मोदी की ड्रेस में व कुछ विजय शंख लेकर पहुंचे। जैसे-जैसे चुनावी नतीजे आ रहे थे, वैसे-वैसे कार्यकर्ताओं व समर्थकों में उत्साह बढ़ता जा रहा था। मुख्यालय के आस-पास का इलाका पूरा भगवा नजर आ रहा था। यहां से आने-जाने वाले राहगीर भी भाजपा मुख्यालय की एक झलक देखने को आतुर दिखे। शाम तक कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और लोग गेट के अंदर जाने की कोशिश करते दिखे।

भाजपा अपनी जीत को लेकर मानो आश्वस्त थी, ऐसे में मुख्यालय से लेकर प्रदेश कार्यालय में पहले से ही प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर से पटा है। जगह-जगह लाउड स्पीकर और स्क्रीन लगाई गई है। पोस्टर में मोदी की राजनीति के सफर की झलकियां दिखाई गई हैं। जिसमें वह नए संसद भवन के निर्माण से लेकर राम मंदिर के उद्घाटन की तस्वीरों को दिखाया है। ऐसे में समर्थक और कार्यकर्ता उनके पोस्टर के साथ सेल्फी भी लेते दिखे।

मोदी की आरती उतारी, चढ़ाया दूध

बिहार के हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से साइकिल चलाकर भाजपा मुख्यालय पहुंचे रतन रंजन ने अपनी साइकिल पर मोदी का कटआउट लगाया है। वह मोदी की पहले आरती करते हैं। इसके बाद उन्हें दूध चढ़ाते हैं। यह देश हर कोई उनके साथ सेल्फी लेने लगता है और मोदी की आरती उतारने लगाता है। उन्होंने बताया कि वह युवा अवस्था से भाजपा के समर्थक हैं। तीन माह पहले अपने घर से चले थे और आज चुनावी नतीजे आने पर यहां आए हैं। वहीं, इसी तरह शंखनाद करने के लिए मेरठ से संजय गोस्वामी भी पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि जब भी मोदी या योगी जीतते हैं तो वह जरूर मुख्यालय आते हैं।

कांग्रेस में जश्न का माहौल, राहुल गांधी जिंदाबाद के गूंजे नारे

अकबर रोड स्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के मुख्यालय में हर्ष का माहौल दिखा। कांग्रेस कार्यकर्ता ढोल की ताल पर झूमते नजर आए। यहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह प्यार-मोहब्बत की जीत है। इस खास मौके पर मुख्यालय के बाहर पटाखे फोड़े गए। यहां जश्न मनाते और मिठाई बांटते पार्टी के कार्यकर्ताओं से दिखाई दिए। रुझानों और नतीजों के बाद जश्न का माहौल और बढ़ता नजर आया। कार्यकर्ताओं ने नतीजों पर नजर बनाए रखी। जैसे ही कांग्रेस की एक सीट की बढ़त मिलती वैसे ही कार्यकर्ता तालियां बजाने लगते हैं। वहीं, जैसे ही एक सीट कम होती है तो मायूस हो जाते हैं। यहां सीट के उतार-चढ़ाव पर शोर गुल नजर आया। इसी के साथ राहुल गांधी जिंदाबाद के नारों से गूंजे।

लोग यहां कांग्रेस के चिन्ह के कपड़े, झंडे लेकर पहुंचे थे। कई समर्थन अपने परिवार के साथ भी यहां पहुंचे। रुझान के बाद तस्वीर जैसे-जैसे साफ हो रही थी, वैसे ही कांग्रेस मुख्यालय के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं का जमवाड़ा बढ़ रहा था और लोग ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मना रहे थे। आलम यह था कि कार्यकर्ताओं की अधिक संख्या को देख मुख्यालय के मुख्य गेट को बंद कर दिया गया। नाचते गाते कार्यकर्ता हाथों में कांग्रेस का झंडा लेकर फहरा रहे थे और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जिंदाबाद के नारे लगाकर जश्न मना रहे थे। कांग्रेस मुख्यालय परिसर में तो सुबह से ही पूरी और भटूरे बन रहे थे और परिसर में मौजूद नेता कार्यकर्ता उसका स्वाद ले रहे थे।

सन्नाटे के साय में रहा आप मुख्यालय

लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर जहां भाजपा व कांग्रेस मुख्यालय में सुबह से भी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा रहा। वहीं, यहां से कुछ ही दूरी पर स्थित आम आदमी पार्टी (आप) मुख्यालय सूना पड़ा रहा है। यहां न जश्न की कोई तैयारी दिखी, न ही किसी तरह साज-सज्जा। न फूल व गुब्बारें लगे दिखे। ऐसे में चुनाव के रुझान आने से पहले भी जश्न फीका नजर आया। हर तरफ सन्नाटा छाया रहा। पार्टी मुख्यालय में नेता तो दूर कार्यकर्ताओं की भी चहल कदमी नहीं दिखी। पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा भी समय पर कर दी थी। जोर-शोर से प्रचार भी किया। लेकिन, उसके बावजूद दिल्ली में लोकसभा सीट पर कोई जीत दर्ज नहीं की गई।

फिर से क्लीन स्वीप राजधानी दिल्ली में भाजपा

राजधानी दिल्ली की सभी सात लोकसभा सीटों पर हुए चुनाव के नतीजों के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटों की गिनती आठ बजे शुरू हो गई। दिल्ली में मतगणना के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गए हैं।

उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी जीते

उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा के मनोज तिवारी ने जीत दर्ज कर ली है। उन्होंने यहां से कांग्रेस के कन्हैया कुमार को हराया। बता दें दिल्ली में भाजपा से केवल एक मात्र मनोज तिवारी ही थे जिनका टिकट पार्टी ने नहीं काटा था और पार्टी का यह फैसला सही साबित भी हुआ।

पूर्वी दिल्ली में जीते हर्ष मल्होत्रा

पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा के हर्ष मल्होत्रा जीत गए हैं। उन्होंने इस सीट पर 91000 से अधिक मतों से जीत हासिल की। यहां उनका मुकाबला आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार से था।

चांदनी चौक पर लहरा भगवा

चांदनी चौक लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल ने जीत हासिल कर ली है। इस सीट पर उन्होंने कांग्रेस के जेपी अग्रवाल को माद दी। उन्होंने 89000 वोट से अधिक अतंर से इस लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की।

उत्तर पश्चिमी दिल्ली से योगेंद्र चंदोलिया जीते

उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार योगेंद्र चंदोलिया ने जीत दर्ज कर ली है। इस सीट पर उन्हें कांग्रेस के उदित राज से टक्कर मिली।

दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट से रामवीर सिंह बिधूड़ी जीते

दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार रामवीर सिंह बिधूड़ी ने जीत दर्ज कर ली है। इस सीट पर उन्हें आम आदमी पार्टी के सहीराम पहलवान से टक्कर मिली।

प्रियंका के घर के बाहर जश्न

दिल्ली में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के घर के बाहर समर्थकों ने ढोल और नगाड़ों के साथ मनाया जश्न।

नई दिल्ली सीट से भाजपा की बांसुरी स्वराज जीतीं

नई दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा की बांसुरी स्वराज ने जीत दर्ज कर ली है। इस सीट पर उसके सामने आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती चुनाव लड़ रहे थे।

उत्तर पश्चिमी दिल्ली में भाजपा 200000 मतों से आगे

पश्चिमी दिल्ली में भाजपा की लीड 138000 हुई है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली में भाजपा करीब 200000 मतों से आगे है। वहीं चांदनी चौक में भाजपा 42000 वोट से आगे चल रही है।

चांदनी चौक में एक बार फिर भाजपा की लीड कम हुई

पश्चिमी दिल्ली में 132000 की बीजेपी की लीड हुई। चांदनी चौक में एक बार फिर भाजपा की लीड कम हुई। अब यहां करीब 34000 वोटों से भाजपा आगे चल रही है। उत्तर पश्चिम दिल्ली में भाजपा की लीड 183000 हुई।

उत्तर पश्चिम दिल्ली में भाजपा पौने दो लाख वोटों से आगे

चांदनी चौक में भाजपा की लीड 36000 से अधिक हुई। उत्तर पश्चिम दिल्ली में भाजपा की लीड पौने दो लाख हुई।

दिल्ली में फिर नहीं खुला किसी तीसरे दल का खाता, इस बार 148 प्रत्याशियों की जमानत जब्त

इस लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सात लोकसभा सीटों के लिए 162 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। भाजपा और आईएनडीआई गठबंधन के प्रत्याशियों के अलावा बीएसपी ने भी सातों सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे थे। लेकिन हाथी की चाल बेहद कमजोर रही। इस वजह से बीएसपी के दो उम्मीदवारों को छोड़कर बीएसपी के अन्य उम्मीदवार दस हजार मत भी नहीं पा सके।

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा और आईएनडीआईए (कांग्रेस व आम आदमी पार्टी) के प्रत्याशियों के बीच जोरदार मुकाबला हुआ। इस मुकाबले में भाजपा न सिर्फ भारी पड़ी बल्कि राष्ट्रीय राजधानी में लगातार तीसरी बार क्लीन स्वीप किया। भाजपा और प्रतिद्वंदी आईएनडीआईए प्रत्याशियों के अलावा अन्य दलों के एक भी उम्मीदवार और निर्दलीय अपनी जमानत नहीं बचा पाए।

बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के सातों उम्मीदवारों सहित 148 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। खास बात यह कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) के बीच गठबंधन होने के बावजूद इस बार भी दिल्ली में किसी तीसरे दल का खाता नहीं खुल पाया।

35 वर्षों में किसी तीसरे दल को नहीं मिली सीट

दिल्ली में पिछले 35 वर्षों में किसी तीसरे दल को एक भी सीट नहीं मिली। इस दौरान पिछले दस वर्षों में दिल्ली की सात लोकसभा सीटों के लिए हुए तीन चुनावों का परिणाम एकतरफा ही रहा है। बाकी चुनावों में भाजपा व कांग्रेस के प्रत्याशी ही चुनाव जीत पाए थे।

दिल्ली में आखिरी बार वर्ष 1989 के लोकसभा चुनाव में तीसरे दल के रूप में जनता दल ने एक सीट पर जीत दर्ज की थी। तब बाहरी दिल्ली लोकसभा सीट से जनता दल के प्रत्याशी तारीफ सिंह चुनाव जीते थे। इसके बाद अब तक नौ चुनाव हो चुके हैं लेकिन दिल्ली में किसी तीसरे दल को सीट नहीं मिली।

इस बार 162 उम्मीदवार थे मैदान में

इस लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सात लोकसभा सीटों के लिए 162 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। भाजपा और आईएनडीआई गठबंधन के प्रत्याशियों के अलावा बीएसपी ने भी सातों सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे थे। लेकिन हाथी की चाल बेहद कमजोर रही। इस वजह से बीएसपी के दो उम्मीदवारों को छोड़कर बीएसपी के अन्य उम्मीदवार दस हजार मत भी नहीं पा सके। सिर्फ दो उम्मीदवार ही दस हजार से थोड़ा अधिक मत पा सके।

दिल्ली की आप सरकार से इस्तीफा देखकर नई दिल्ली से बीएसपी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद को भी छह हजार से कम वोट मिले। इस वजह से उनकी भी जमानत जब्त हो गई। भाजपा, कांग्रेस, आप और बीएसपी के अलावा 141 अन्य उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में थे। जिसमें करीब चार दर्जन पंजीकृत गौर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रत्याशी व निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं। इन सब की जमानत जब्त हो गई।

जमानत बचाने के लिए 16.5 प्रतिशत मत लाना जरूरी

पिछले लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सात लोकसभा सीटों से 164 उम्मीदवार थे। तब विजेता व प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों को छोड़कर तीन अन्य प्रत्याशी अपनी जमानत बचाने में कामयाब रहे थे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जमानत बचाने के लिए लोकसभा क्षेत्र में कुल हुए मतदान का छठा हिस्सा (करीब 16.5 प्रतिशत) वोट लेना होता है। इससे कम वोट मिलने पर प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाती है।

दिल्ली में इस बार के लोकसभा चुनाव व पिछले चार चुनावों में उम्मीदवारों व जमानत जब्त हुए उम्मीदवारों की संख्या

चुनावी वर्ष	उम्मीदवार	जमानत जब्त
2024	162	148
2019	164	147
2014	150	133
2009	160	146
2004	129	115

परिणाम आने के बाद फिर बजेगा चुनावी बिगुल, चार विधायक और एक पार्षद हैं लोकसभा के लिए मैदान में

परिवहन विशेष न्यूज

भाजपा व आप के चार विधायक व एक पार्षद चुनावी मैदान में है। दक्षिण दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में भाजपा व आम आदमी पार्टी ने अपने-अपने विधायक को उम्मीदवार बना रखा है। इनमें से एक का जीतना तय है।

नई दिल्ली। राजधानी में लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद फिर जल्द ही चुनावी बिगुल बजेगा। भाजपा व आप के चार विधायक व एक पार्षद चुनावी मैदान में है। दक्षिण दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में भाजपा व आम आदमी पार्टी ने अपने-अपने विधायक को उम्मीदवार बना रखा है। इनमें से एक का जीतना तय है। इसके अलावा अन्य दो विधायकों व पार्षद के जीतने की स्थिति में उन्हें अपने वर्तमान पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा।

दिल्ली विधानसभा के अगले साल फरवरी-मार्च माह में चुनाव होंगे। इस कारण विधानसभा के कार्यकाल के करीब नौ माह बचे हुए है। ऐसी स्थिति में विधानसभा की सीटें रिक्त होने पर उनका उपचुनाव कराने का मामला चुनाव आयोग पर निर्भर करेगा। हालांकि, हरियाणा में अभी लोकसभा चुनाव के साथ एक विधानसभा की रिक्त सीट पर उपचुनाव कराया गया है, जबकि हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल अक्तूबर माह में खत्म हो रहा है।

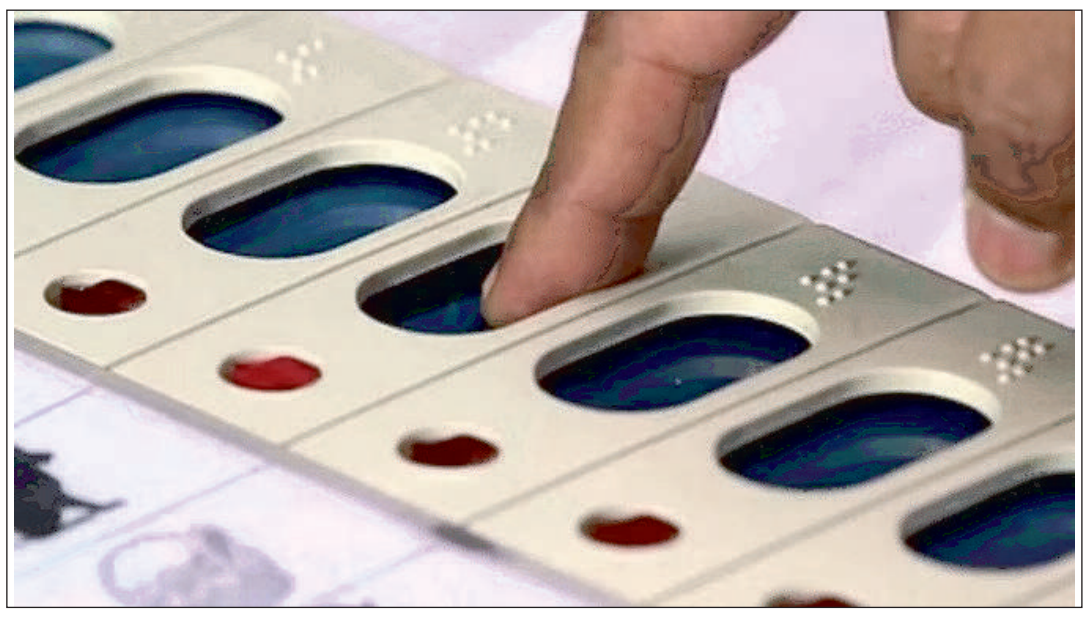

इस तरह दिल्ली में विधानसभा की सीटें रिक्त होने पर उपचुनाव कराने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। वहीं, एमसीडी के चुनाव दिसंबर 2022 में हुए थे। इस कारण एमसीडी के सदन का करीब तीन साल कार्यकाल बचा हुआ है। लिहाजा पार्षद सीट रिक्त होने पर उसका उपचुनाव हर हाल में होगा। इससे पहले एमसीडी के सदन के कार्यकाल के 10 माह बचे होने के बावजूद कई वार्डों का उपचुनाव हो चुका है।

आप के तीन व भाजपा का एक विधायक हैं मैदान में

आम आदमी पार्टी ने अपने तीन विधायकों को लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बना रखा है, जबकि भाजपा ने अपने एक विधायक व एक पार्षद को टिकट दे रखा है। दक्षिण दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से आप व भाजपा के विधायक आमने-सामने है। इस क्षेत्र में आप के सहीराम व भाजपा के रामवीर सिंह बिधूड़ी चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा आप ने अपने विधायक सोमनाथ भारती को नई दिल्ली क्षेत्र व कुलदीप कुमार को पूर्वी दिल्ली क्षेत्र से टिकट दिया।

भाजपा ने द्वारका वार्ड से अपनी पार्षद कमलजीत सहरावत को पश्चिम दिल्ली क्षेत्र से उम्मीदवार बना रखा है। इस तरह मंगलवार को मतगणना के बाद इन नेताओं की हार-जीत से विधानसभा की तीन सीटों व एमसीडी की एक सीट रिक्त होने के बारे में स्थिति साफ होगी। इसके अलावा उनके छोटे सदन से बड़े सदन में पहुंचने के मामले में भी तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी।

दिल्ली में ये क्यों हुआ?: औंधे मुंह गिरा आप-कांग्रेस का गठबंधन, पढ़ें क्या रहे इनकी नाकामी के प्रमुख कारण

दो बड़े नेताओं की कैद व विवादों में रहा आप का चुनावी अभियान सिरे नहीं चढ़ सका। एक साथ कई कारकों ने मिलकर दिल्ली की सातों सीटों को लगातार तीसरी बार भाजपा की झोली में डाल दिया।

भाजपा को शिकस्त देने के लिए आम आदमी पार्टी (आप) व कांग्रेस में बढ़ी नजदीकी जमीन पर काम नहीं कर सकी। दोनों दलों का गठबंधन दिल्ली में धड़ाम हो गया। इसने दिल्ली की सत्ता पर 10 साल से काबिज आप को लगातार तीसरी बार बड़ा झटका दिया। वहीं, कांग्रेस भी इस बीच वापसी नहीं कर सकी। दोनों राजनीतिक पार्टियां मिलकर वोटर को समझाने में नाकाम रहीं। इससे वे अपने वोट दूसरे दल को शिफ्ट करने में नाकाम रहे। दो बड़े नेताओं की कैद व विवादों में रहा आप का चुनावी अभियान सिरे नहीं चढ़ सका। एक साथ कई कारकों ने मिलकर दिल्ली की सातों सीटों को लगातार तीसरी बार भाजपा की झोली में डाल दिया।

बड़े आप नेता जेल में बंद

कथित शराब घोटाले में आप के कई बड़े नेता जेल में बंद हैं। मनीष सिसोदिया व सत्येंद्र जैन लंबे समय से तिहाड़ में हैं। अक्तूबर में सांसद संजय सिंह को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। चुनावों के एलान के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी तिहाड़ पहुंच गए। शुरुआती दौर में इसका असर आप के प्रचार अभियान पर दिखा। मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल को प्रचार अभियान की कमान अपने हाथ में लेनी पड़ी।

मालीवाल प्रकरण भी पड़ा भारी

जब संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए तो ऐसा लग रहा था कि आप की मुहिम रंग दिखाएगी, लेकिन इसी बीच आप सांसद स्वाति मालीवाल का मामला सामने आ गया। मुख्यमंत्री आवास के अंदर मालीवाल से मारपीट के आरोपों पर पूरी पार्टी रक्षात्मक मुद्रा में आ गई। बड़े नेता इस मसले पर जगह-जगह सफाई देते दिखे। अमूमन आक्रामक रहने वाले केजरीवाल ने भी इस पर चुप्पी साध ली। इसके उलट भाजपा ने इसे महिला सुरक्षा का मुद्दा बना लिया। इससे आप के अभियान को धार नहीं मिल सकी।

दिल्ली से मेरठ तक बनाए जाएंगे 900 से ज्यादा वर्षा जल संचयन पिट्स

गाजियाबाद। दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर पर स्थित सभी स्टेशनों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाने का काम तेज हो गया है। दिल्ली के सराय काले खां से लेकर मेरठ तक के बीच आरआरटीएस 900 पिट्स बना रहा है। करीब 75 फीसदी काम पूरा करने का दावा किया गया है। एनसीआरटीसी के सीपीआरओ पुनीत वत्स का कहना है कि वैश्विक पर्यावरण लक्ष्यों के अनुरूप वर्षा जल संचयन के लिए प्रभावी तंत्र तैयार किया जा रहा है। इसके तहत दिल्ली के सराय काले खां से लेकर मेरठ के मोदीपुरम तक के एलिवेटेड वायडक्ट, स्टेशनों और डिपो में 900 से ज्यादा वर्षा जल संचयन पिट्स बनाए जा रहे हैं। इन पिट्स के जरिए लाखों क्यूबिक मीटर ग्राउंड वॉटर रिचार्ज हो सकेगा। स्टेशनों पर भी प्रत्येक प्रवेश-निकास द्वारों के पास दो-दो वर्षा जल संचयन पिट्स विकसित किए जा रहे हैं। इस कॉरिडोर पर ट्रेनों के रखरखाव और संचालन के लिए दो डिपो होंगे। एक डिपो दुहाई, गाजियाबाद में बनकर तैयार हो चुका है और दूसरा मोदीपुरम मेरठ में निर्मित किया जा रहा है। दुहाई डिपो में 20 से ज्यादा वर्षा जल संचयन पिट्स बनाए गए हैं। इन पिट्स की गहराई लगभग 16 से 22 मीटर भूजल स्तर के मुताबिक रखी गई है। इस सिस्टम की मदद से भूजल स्तर को बढ़ाने में सहयोग मिलेगा।

गाजियाबाद में बड़ा हादसा: दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक से टकराई डबल डेकर बस, 35 घायल

परिवहन विशेष न्यूज

मोदीनगर में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर ट्रक डबल डेकर बस की टक्कर से 35 घायल हो गए हैं। बस में महाराष्ट्र के श्रद्धालु बैठे हुए थे।

नई दिल्ली। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे पर भोजपुर थाना क्षेत्र के कलछीना गांव के समीप मंगलवार सुबह हरिद्वार से दिल्ली की तरफ जा रही जा रही डबल डेकर बस ट्रक से टकरा गई। हादसे में बस सवार 35 श्रद्धालु घायल हो गए।

घायल श्रद्धालुओं को उपचार के लिए मोदीनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां 22 को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। गंभीर रूप से 13 घायलों को मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। श्रद्धालु महाराष्ट्र के रहने वाले हैं।

वह सभी एक महीने की धार्मिक यात्रा पर निकले थे। श्रद्धालु सोमवार रात हरिद्वार से मथुरा वृंदावन के लिए चले थे। हादसे के बाद आरोपी चालक ट्रक सहित फरार हो गया। मौके पर पहुंची एक्सप्रेस-वे की पेट्रोलिंग टीम ने घायल श्रद्धालुओं को अस्पताल पहुंचाया।

हादसे में बस चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। चिकित्सकों के अनुसार, उसके दोनों पैरों की हड्डियां टूट गई। श्रद्धालुओं के मुताबिक, घटना के काफी देर तक वह एक्सप्रेसवे पर तड़पते रहे। बस में करीब 50 श्रद्धालु थे।

स्विमिंग पूल में डूबने से छह साल की बच्ची की मौत, पुलिस बोली यह लापरवाही का मामला

राजनगर एक्सटेंशन की ब्रेव हार्ट सोसाइटी के स्विमिंग पूल में डूबने से छह साल की मासूम बच्ची खुशबू की मौत हो गई। घटना सोमवार शाम करीब साढ़े सात बजे की है। पुलिस का कहना है कि उन्हें रात करीब सवा आठ बजे घटना की सूचना मिली। हादसा उसे समय हुआ जब बच्ची अकेले ही स्विमिंग पूल में तैरने के लिए आ गई।

गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन की ब्रेव हार्ट सोसाइटी के स्विमिंग पूल में डूबने से छह साल की मासूम बच्ची खुशबू की मौत हो गई। घटना सोमवार शाम करीब साढ़े सात बजे की है। पुलिस का कहना है कि उन्हें रात करीब सवा आठ बजे घटना की सूचना मिली। हादसा उसे समय हुआ जब बच्ची अकेले ही स्विमिंग पूल में तैरने के लिए आ गई।

पुलिस के मुताबिक सिद्धार्थ नगर के मूल निवासी प्रापर्टी डीलर साहिबान अली बीते करीब पांच साल से राजनगर एक्सटेंशन की ब्रेव हार्ट सोसायटी में पत्नी और जुड़वा बेटियों छह वर्षीय खुबशू अली और महक अली के साथ रहते हैं। सोमवार शाम करीब साढ़े सात बजे उनकी बेटी खुशबू अली सातवें फ्लोर स्थित फ्लैट से नीचे स्विमिंग पूल पर आई और पूल में उतर गई।

कुछ ही देर में बच्ची पानी मे डूब गई और उसका शरीर पानी के उपर आ गया। यह देख वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। बच्ची के स्वजन को मामले की सूचना दी गयी। मौके पर स्वजन ने पहुचकर बच्ची को नजदीकी चिकित्सक को दिखाया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि मामले में एओए की लापरवाही लग रही है। क्योंकि मौके पर गार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए।

स्विमिंग पूल में बच्ची के डूबने की सूचना मिलने पर पुलिस गयी थी, लेकिन बच्ची की मृत्यु हो चुकी थी। मामले में अभी कोई शिकायत नहीं मिली है।

रवि कुमार सिंह, एसीपी नंदग्राम

एसीपी की गाड़ी से दूसरी कार में लगी टक्कर

सोमवार देर रात एसीपी कानून व्यवस्था अजीत कुमार रजक की सरकारी गाड़ी की शास्त्री नगर चौराहे पर दूसरे वाहन से टक्कर लग गयी। घटना में पांच लोगों के चोट आई हैं। एसीपी अजीत कुमार रजक का कहना है कि गाड़ी में उनके गनर और चालक थे। दोनों उन्हें आवास पर छोड़कर रात करीब 12 बजे जा रहे थे। टक्कर लगने की जानकारी है, लेकिन एक ही घायल की सूचना उनके पास है। एसीपी कविनगर अभिषेक श्रीवास्तव का कहना है कि घटना में पांच लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। अभी किसी पक्ष ने थाने में शिकायत नहीं दी है।

पेयजल समस्या के समाधान के लिए वार्डस्तर पर सौंपी जिम्मेदारी

गुरुग्राम। नगर निगम क्षेत्र में भीषण गर्मी में पेयजल आपूर्ति संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए वार्ड स्तर पर कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी हुई है। निगम ने कर्मचारियों के मोबाइल नंबर भी जारी किए हैं। शहरवासी अपने वार्ड से संबंधित कर्मचारी से मोबाइल पर संपर्क करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। निगमायुक्त डा. नरहरि सिंह बांगड़ के निर्देश पर वार्ड-1, 2 और 7 की सुपरवाइजर अमित कुमार (8901272801), वार्ड नंबर 8, 9 व 17 की सुपरवाइजर अशोक कुमार (8396963099), वार्ड नंबर 13, 20, 21, 22, 23, 24 की सुपरवाइजर दीपक (8383080586), वार्ड नंबर 10, 11, 12, 14, 15 व 16 की कनिष्ठ अभियंता रोहित कुमार (9671895169) व सुपरवाइजर कृष्ण (9210215152) को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी प्रकार वार्ड- 3, 4, 5, 6, 18 व 19 में सुपरवाइजर प्रवीण (7053780189), वार्ड-28, 29 व 30 में कनिष्ठ अभियंता राहुल खान (9821395267), वार्ड-31 व 32 में सुपरवाइजर साहिल (9050142102), वार्ड-33, 34 व 35 में कनिष्ठ अभियंता (9971070036) तथा वार्ड-25, 26 व 27 में कनिष्ठ अभियंता कपिल (9728822849) को तैनात किया गया है।

मुंबई एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराई बाइक, चाचा-भतीजे की मौत

सोहना। मुंबई-बड़ोदरा एक्सप्रेसवे पर गांव दौहला के समीप डिवाइडर से बाइक टकराने से चाचा-भतीजे की मौत हो गई। दोनों गुरुग्राम में खाना बनाने का काम करते थे। पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम सोहना के नागरिक अस्पताल में कराकर परिजनों को सौंप दिए।

बिहार के मधुबनी निवासी 40 वर्षीय अशोक व उनका भतीजा 16 वर्षीय सुजीत गुरुग्राम में खाना बनाने का काम करते थे। अशोक व सुजीत दोनों एक बाइक से सोहना में दोस्तों से मिलने आए थे लेकिन रास्ता भटक गए और मुंबई एक्सप्रेसवे पर चढ़ गए। गांव दोहला के नजदीक उनकी बाइक डिवाइडर से टकरा गई। बाइक ज्यादा स्पीड में होने के कारण काफी दूर तक घिसटती चली गई। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।

दुर्घटना को देख राहगीरों ने मृतकों के शव को एक साइड में रख दिया व सोहना पुलिस को सूचित कर दिया। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी जगजीत सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों शवों का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिए। इस मामले में थाना प्रभारी जगजीत सिंह ने बताया कि दोनों के शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। बता दें कि एक्सप्रेसवे पर बाइक समेत कई तरह के वाहनों पर प्रतिबंध है।

नई सरकार के सामने 'ए.आई.' और जलवायु परिवर्तन की बड़ी चुनौती

आखिरी चरण के मतदान के पहले ओपन ए.आई. कम्पनी ने खुलासा किया कि इसराईल और दूसरे देशों से चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की गई। चुनाव प्रचार के दौरान चैट जी.पी.टी. और दूसरे ए.आई. प्लेटफार्म के माध्यम से झूठी कहानियां गढ़ी गईं।

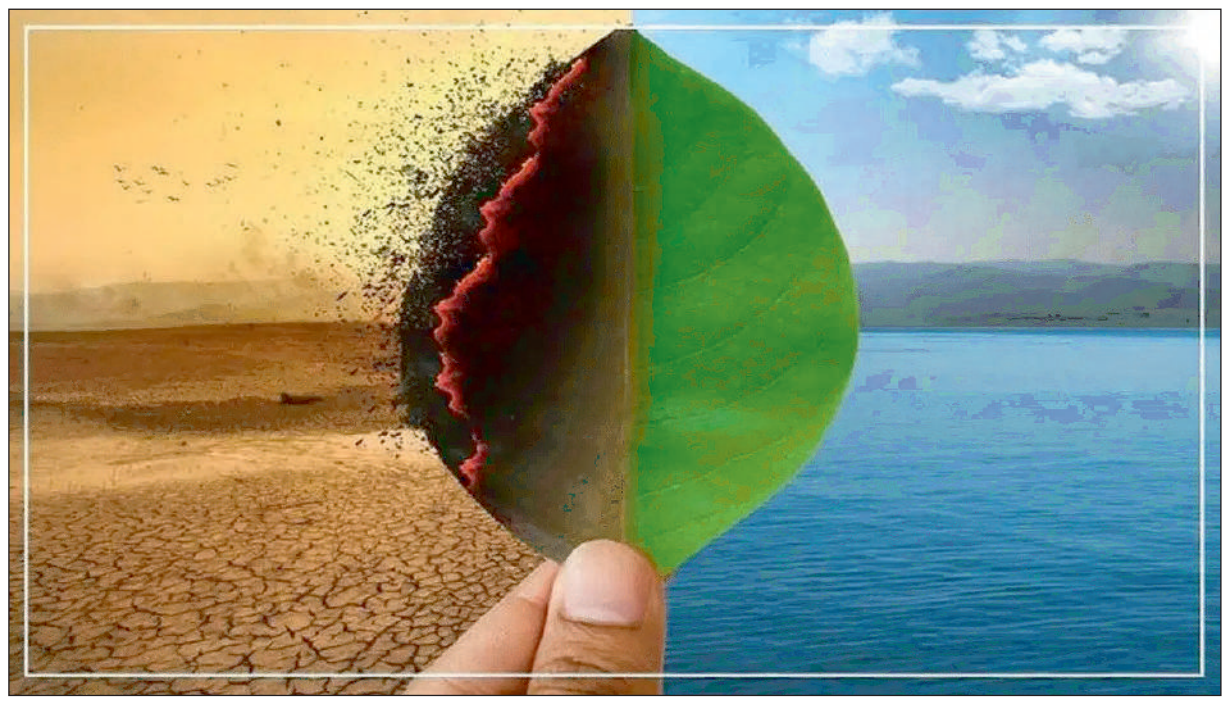

भारत में सभी शहर कचरों के पहाड़ बन गए हैं। नगर पालिका और एम .सी .डी . इस बदहाली की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर ठेल देते हैं। राज्य सरकारें इसके लिए केन्द्र सरकार को जवाबदेह ठहरा देती हैं। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में सतही पी .आई .एल . फाइल होने के बाद हो-हल्ला भी मचता है लेकिन जमीनी हकीकत बद से बदतर हो रही है। पैरिस और दुबई में जलवायु परिवर्तन से जुड़ी कांफ्रेंस में जीवाश्म ईंधन पर काबू पाने जैसे मामलों पर ठोस बहस हुई लेकिन भारत में प्रदूषण नियंत्रण, ई-वेस्ट, प्लास्टिक और सोलर वेस्ट से जुड़े नियम सिर्फ कानून की किताबों में कैद हैं।

आखिरी चरण के मतदान के पहले ओपन ए.आई. कम्पनी ने खुलासा किया कि इसराईल और दूसरे देशों से चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की गई। चुनाव प्रचार के दौरान चैट जी.पी.टी. और दूसरे ए.आई. प्लेटफार्म के माध्यम से झूठी कहानियां गढ़ी गईं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और एक्स आदि सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से फेक और झूठे कंटैंट का प्रसार करके मतदाताओं को भरमाने का प्रयास किया गया। भाजपा और संघ समर्थकों के अनुसार यू-ट्यूब के माध्यम से सरकार विरोधी कंटैंट को फैलाने में गूगल इंडिया के कर्मचारियों ने मदद की। साइबर अपराधों पर रोकथाम और ए.आई. (कृत्रिम बुद्धिमता) पर नियमन नई सरकार के सर्वोच्च एजैंडे में शामिल हैं।

दूसरा बड़ा मुद्दा जलवायु परिवर्तन से जुड़ा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बढ़ते तापमान को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि वह दिन दूर नहीं जब देश की राजधानी रेगिस्तान बन जाएगी। उत्तर भारत में लू और आग की घटनाओं को रोकने, दक्षिण भारत में रेमल चक्रवात से निपटने और उत्तर-पूर्व भारत में बाढ़ और भू-स्खलन से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए हैं।

जलवायु परिवर्तन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला : चुनाव रिजल्ट पर तस्वीर साफ होने के साथ विश्व पृथ्वी दिवस के मौके पर नई सरकार का आगाज होगा। प्रधानमंत्री मोदी साल 2047 में नए भारत की तस्वीर को गढने की कोशिश कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी के प्रोजैक्ट में खरबों रुपए खर्च हो रहे हैं जबकि हकीकत में दिल्ली समेत देश के दूसरे महानगरों और गांवों, कस्बों में जलवायु परिवर्तन की वजह से लोगों को जान के लाले पड़ रहे हैं। दिल्ली सरकार पानी की किल्लत के लिए पड़ोसी राज्यों को जिम्मेदार ठहरा रही है लेकिन अधिकांश राज्य भयानक जल संकट से जूझ रहे हैं। सोशल मीडिया में वायरल हो रही पोस्ट के अनुसार दुनिया में प्रति व्यक्ति 422 पेड़ की तुलना में भारत में प्रति व्यक्ति 28 पेड़ ही हैं। इंगलैंड में 47, चीन में 130, अमरीका में 699, ऑस्ट्रेलिया में 3266 और कनाडा में 10163 प्रति व्यक्ति पेड़ होने का दावा किया जा रहा है।

भारत में सभी शहर कचरों के पहाड़ बन गए हैं। नगर पालिका और एम.सी.डी. इस बदहाली की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर ठेल देते हैं। राज्य सरकारें इसके लिए केन्द्र सरकार को जवाबदेह ठहरा देती हैं। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में सतही पी.आई.एल. फाइल होने के बाद हो-हल्ला भी मचता है लेकिन जमीनी हकीकत बद से बदतर हो रही है। पैरिस और दुबई में जलवायु परिवर्तन से जुड़ी कांफ्रैंस में जीवाश्म ईंधन पर काबू पाने जैसे मामलों पर ठोस बहस हुई लेकिन भारत में प्रदूषण नियंत्रण, ई-वेस्ट, प्लास्टिक और सोलर वेस्ट से जुड़े नियम सिर्फ कानून की किताबों में कैद हैं।

2 महीने पहले अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में जलवायु परिवर्तन को समानता और जीवन के अधिकार के साथ जोड़ा था। उसके अनुसार लोगों को स्वस्थ पर्यावरण में रहने का संवैधानिक अधिकार है लेकिन ऐसे फैसलों पर मीडिया में ज्यादा चर्चा नहीं होती। 7 चरणों के चुनावों में जल, जंगल, जमीन और जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर नेताओं और जनता में कोई जागरूकता नहीं दिखी। सरकारें भी वोट बैंक के शॉर्टकट के अनुसार रेवडियां बांटने में ज्यादा मस्त रहती हैं। सरकारी सुविधाओं और रेवडियों की होड़ में लाभार्थी बन रहे समाज में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का पूरी तरह से अभाव है। गांवों की कृषि अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सरकार, सुप्रीम कोर्ट और संसद के ट्रिपल इंजन को एकजुट होकर दीर्घकालिक रणनीति से मुकाबला करने की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन के दुष्चक्र से यदि शहर भी मौत की भट्ठी बन गए तो फिर 140 करोड़ की आबादी वाले देश में विकसित भारत का सपना कैसे साकार होगा?

ए.आई. और डिजिटल की चुनौती : इस बार के चुनाव यू-ट्यूब और व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से लड़े गए। विदेशी डिजिटल कम्पनियों के नियमन के लिए हमारे प्रतिवेदन पर चुनाव आयोग ने साल 2013 में गाइडलाइंस जारी की थीं, जिन पर लापता जैंटलमैनों (चुनाव आयुक्तों) के दौर में अमल ही नहीं होता। सभी प्लाटयों के आई.टी. सैल और नेताओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव आयोग की आचार संहिता का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन किया। इसके लिए ए.आई. के माध्यम से बड़े पैमाने पर फर्जी और झूठी सामग्री बनाई गई। डीपफेक की बाढ़ को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने 70 लोगों की टीम बनाई थी। उन्होंने बड़े इन्फ्लुएंसर्स के सोशल मीडिया को खंगाल कर फैक्ट चैक करने की कोशिश की लेकिन पूरे चुनावी प्रचार के दौरान ए.आई. जेनरेटिड वीडियो, ऑडियो, मैसेज और फोटो की बाढ़ थी। मतदान के 48 घंटे पहले के साइलैंस पीरियड में नेताओं ने सोशल मीडिया से चुनाव प्रचार कर आचार-संहिता की धज्जियां उड़ाईं।

भारत में डाटा सुरक्षा कानून और उसके नियम लागू नहीं हैं और ए.आई. पर कई सालों से कानून बनाने की चर्चा हो रही है। कानून लागू नहीं होने और प्रभावी रैगुलेटर की कमी की वजह से भारत डाटा चोरी और साइबर अपराध की सबसे बड़ी मंडी बन गया है। चुनावों के दौरान दुनिया के सबसे रइस व्यक्ति मस्क ने फेसबुक और व्हाट्सएप वाली मेटा कम्पनी पर डाटा चोरी का आरोप लगाया। टेस्ला और एक्स के मालिक मस्क के इन आरोपों पर भारत में मीडिया रिपोर्टिंग और चुनावी बहस नहीं होना निराशाजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। 2007 के बाद 'ऑप्रेशन प्रिज्म' के तहत अमरीकी खुफिया एजैंसियों ने भारत का बड़े पैमाने पर डाटा चुराया। डाटा चोरी, अराजक सोशल मीडिया और ए.आई. के गैर-कानूनी इस्तेमाल से वोटिंग और रिजल्ट को प्रभावित करने का ट्रैंड जारी रहा तो भारतीय लोकतंत्र और सरकारें विदेशी कम्पनियों की गिरफ्त में आ सकती हैं।

-विराग गुप्ता (एडवोकेट, सुप्रीम

होण्डा ने बेचे 4.92 लाख दो पहिया वाहन, मिली 49 फीसदी की ग्रोथ, जानें पूरी डिटेल

भारतीय बाजार में जापानी दो पहिया वाहन निर्माता Honda के स्कूटर और बाइक स को काफी पसंद किया जाता है। कंपनी Activa स्कूटर से लेकर Shine जैसी बाइक स को ऑफर करती है। कंपनी की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक May 2024 के दौरान करीब पांच लाख वाहनों की बिक्री हुई है। कंपनी को बिक्री के मामले में कितनी ग्रोथ मिली है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। जापानी दो पहिया वाहन निर्माता Honda Motorcycle and Scooter India ने बीते महीने करीब पांच लाख वाहनों की बिक्री की है। कंपनी की ओर से May 2024 के दौरान कितने वाहनों की घरेलू बाजार में बिकी की है और कितनी यूनिट्स का एक्सपोर्ट किया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

कितनी हुई बिक्री

होंडा कंपनी की ओर से May 2024 के दौरान कुल 492047 यूनिट्स दो पहिया वाहनों की बिक्री की गई है। कंपनी ने आंकड़ों के मुताबिक ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 49 फीसदी की बढ़ोतरी हासिल की है।

घरेलू बाजार और एक्सपोर्ट में कैसा प्रदर्शन

कंपनी की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक होंडा ने घरेलू बाजार में बीते महीने के दौरान कुल 450589 यूनिट्स वाहनों की बिक्री की है। जबकि कंपनी ने 41458 यूनिट्स का एक्सपोर्ट भी किया है। जानकारी के मुताबिक होंडा ने घरेलू बाजार में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 45 फीसदी और एक्सपोर्ट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 127 फीसदी की बढ़त बनाई है।

Honda Shine ने बनाया रिकॉर्ड

कंपनी की एंट्री सेगमेंट की बाइक होंडा शाइन ने हाल में ही नया रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी ने इस बाइक को पिछले साल 100 सीसी सेगमेंट में लॉन्च किया था, जिसने एक साल में तीन लाख बाइक्स की बिक्री का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस बाइक के साथ ही कंपनी ने 100 सीसी सेगमेंट में अपनी मौजूदगी को काफी बढ़ाया है।

कई राज्यों में रही 125 सीसी बाइक स की मांग

कंपनी के पोर्टफोलियो में 100 सीसी के साथ ही 125 सीसी की बाइक्स भी मौजूद हैं। इन बाइक्स में शाइन 125 और एसपी 125 को भी बीते एक साल में कई राज्यों में काफी पसंद किया गया है। कंपनी के मुताबिक बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में इस सेगमेंट की बाइक्स ने 30 लाख से ज्यादा की बिक्री का आंकड़ा पार किया है।

कैसा है पोर्टफोलियो

होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटर इंडिया की ओर से भारतीय बाजार में कई बेहतरीन बाइक्स और स्कूटर को ऑफर किया जाता है। जिनमें CB200X, Hornet Repsol, Horent 2.0, SP160, Unicorn, SP125, SP125Sports, Shine125, Livo, CD110 Dlx, Shine100 जैसी बाइक्स शामिल हैं। इनके अलावा प्रीमियम बाइक्स के तौर पर कंपनी CB350, CB300R, CB300F, NX500, XL750 Transalp, Gold Wing Tour को ऑफर करती है। कंपनी की ओर से Dio125, Dio 125 Repsol Edition, Activa Spl Edition, Activa 125, Activa और Dio जैसे स्कूटर को ऑफर किया जाता है।

मई 2024 में कैसा रहा बजाज ऑटो की बिक्री का मिजाज, अब है कंपनी की ये प्लानिंग

बजाज की ओर से जारी की गई रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा गया कि कंपनी ने पिछले साल मई में 3 .55 लाख यूनिट्स की बिक्री थी और इस बार भी आंकड़ा 3 .55 लाख पर ही रहा है। पिछले साल 355148 यूनिट्स बेची गई थीं। जबकि इस साल यह संख्या मामूली सी बढ़कर 355323 हो गई है। कंपनी 18 जून को सीएनजी बाइक लॉन्च करने वाली है।

नई दिल्ली। ऑटो कंपनियों ने मई 2024 के बिक्री के आंकड़े जारी कर दिए हैं। कुछ कंपनियों की बिक्री पिछले साल की समान अवधि की तुलना में बढ़ी है तो कुछ की बिक्री में गिरावट देखी गई है।

बजाज ऑटो ने भी अपने बिक्री के आंकड़े जारी कर दिए हैं। जारी किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि बजाज ऑटो ने पिछले साल और इस साल उसी अवधि में लगभग एक जैसा ही काम किया है।

कितनी हुई बजाज की बिक्री

बजाज की ओर से जारी की गई रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा गया कि कंपनी ने पिछले साल मई में 3.55 लाख यूनिट्स की बिक्री थी और इस बार भी आंकड़ा 3.55 लाख पर ही रहा है। पिछले साल 3,55,148 यूनिट्स बेची गई थीं। जबकि इस साल यह संख्या मामूली सी बढ़कर 3,55,323 हो गई है।

एक्सपोर्ट में हुई बढ़ोत्तरी

निर्माता की डॉमेस्टिक सेल्स (कमर्शियल व्हीकल सहित) 1 प्रतिशत गिर गई है। मई 2023 में 3,55,148 यूनिट्स की बिक्री हुई थी। जबकि इस बार यह आंकड़ा 2,25,087 यूनिट्स पर आ गया है। मई महीने में 3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी देखने को मिली है। पिछले वर्ष समान अवधि में 1,26,747 वाहन विदेशी बाजारों में भेजे गए थे। जबकि इस बार 1,30,236 यूनिट्स एक्सपोर्ट हुई हैं।

जल्द लॉन्च होगी CNG बाइक

दोपहिया वाहन निर्माता बजाज ऑटो 18 जून को दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च करने वाली है। इस बात की पुष्टि कुछ दिन पहले ही बजाज ऑटो के मैनेजिंग डायरेक्टर Rajiv Bajaj ने की थी। CNG Bike को निर्माता के द्वारा रूरल और सेमी अर्बन एरिया में रहने वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए लाया जा रहा है।

बता दें कुछ दिन पहले बजाज ने Glider, Marathon, Trekker और Freedom को ट्रेडमार्क कराया है। इससे पता चलता है कि कंपनी के पोर्टफोलियो में कई और प्रोडक्ट भी शामिल हो सकते हैं।

एक लाख रुपये की डॉउन पेमेंट के बाद घर लाएं हुंडई एक्स्टर SUV, जानें कितनी देनी होगी EMI

साउथ कोरियाई वाहन निर्माता की ओर से माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में Exter को ऑफर किया जाता है। कंपनी की इस कार को देश में बड़ी संख्या में लोग पसंद कर रहे हैं। अगर आप भी इसे खरीदने का मन बना रहे हैं तो इसके बेस वेरिएंट EX को एक लाख रुपये की Down Payment के बाद कितने साल की EMI पर घर लाया जा सकता है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। देश की प्रमुख कार निर्माता Hyundai की ओर से Exter SUV को भारतीय बाजार में ऑफर किया जाता है। हर महीने बड़ी संख्या में लोग इस कार को खरीदते हैं। अगर आप भी इसे खरीदने का मन बना रहे हैं, तो हर महीने कितने रुपये की EMI देकर इसे घर लाया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

कितनी है कीमत

Hyundai की ओर से Exter के Ex वेरिएंट को 6.13 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर ऑफर किया जा रहा है। इसे दिल्ली में खरीदने पर कुल 6.95 लाख रुपये देने होंगे। इस कीमत में 6.13 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत के अलावा 49196 रुपये आरटीओ और इंश्योरेंस के 31944 और 850 रुपये फास्टैग और नंबर प्लेट के चार्ज भी शामिल हैं।

एक लाख रुपये Down Payment के बाद कितनी EMI

अगर इस गाड़ी के EX वेरिएंट को आप खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में एक लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 5.95 लाख रुपये की राशि को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको 8.7 फीसदी ब्याज के साथ सात साल के लिए 5.95 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने सिर्फ 9483 रुपये हर महीने की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।

कितनी महंगी पड़ेगी कार

अगर आप 8.7 फीसदी की ब्याज दर के साथ सात साल के लिए 5.95 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 9483 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Exter के लिए करीब 2.01 लाख रुपये बतौर ब्याज देंगे। जिसके बाद आप कार की कुल कीमत एक्स शोरूम, ऑन रोड और ब्याज मिलाकर करीब 9.14 लाख रुपये देंगे।

Taigun और Virtus के सभी वेरिएंट में मिलेंगे 6 एयरबैग, Volkswagen India ने कर ली तैयारी

परिवहन विशेष न्यूज

भारत 2.0 उत्पाद पोर्टफोलियो की शुरुआत के बाद से कंपनी ने कहा कि वह लगातार अपने उत्पाद पेशकशों को बढ़ा रही है और भारत में अपनी कारों की ग्राहकों की मांग को ध्यान में रखते हुए अपने वेरिएंट लाइन-अप का विस्तार किया है। फॉक्सवैगन इंडिया ने सोमवार को कहा कि वह अपने 5-स्टार ग्लोबल एनसीएपी (GNCAP) सुरक्षा-रेटेड ताइगुन और वर्टस मॉडल के सभी वेरिएंट में छह एयरबैग पेश करेगी।

मुंबई। जर्मन प्रीमियम कार निर्माता कंपनी फॉक्सवैगन इंडिया ने सोमवार को कहा कि वह अपने 5-स्टार ग्लोबल एनसीएपी (जीएनसीएपी) सुरक्षा-रेटेड ताइगुन और वर्टस मॉडल के सभी वेरिएंट में छह एयरबैग पेश करेगी।

भारत 2.0 उत्पाद पोर्टफोलियो की शुरुआत के बाद से कंपनी ने कहा कि वह लगातार अपने उत्पाद पेशकशों को बढ़ा रही है और भारत में अपनी कारों की ग्राहकों की मांग को ध्यान में रखते हुए अपने वेरिएंट लाइन-अप का विस्तार किया है।

जबकि सबकॉम्पैक्ट क्रॉसओवर एसयूवी ताइगुन को सितंबर 2021 में भारत में लॉन्च किया गया था, थीम-साइज सेडान वर्टस को मार्च 2022 में लॉन्च किया गया था। भारत 2.0 कारों के हमारे पोर्टफोलियो में पूरे लाइन-अप में मानक के रूप में छह एयरबैग पेश किए जाएंगे। इसके साथ हम सुरक्षित गतिशीलता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं।

फॉक्सवैगन पैसेंजर कार्स इंडिया के ब्रांड निदेशक आशीष गुप्ता ने कहा हम ताइगुन और वर्टस (उनके परिचय के बाद से) द्वारा 1 लाख से अधिक बिक्री मील का पत्थर हासिल करने पर भी प्रसन्न हैं। हाल ही में फॉक्सवैगन इंडिया ने 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ ताइगुन जीटी लाइन और 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल विकल्प के साथ जीटी प्लस स्पोर्ट के दो नए वेरिएंट पेश किए हैं।

स्कोडा इंडिया ने अपडेट के साथ अपने दोनों मॉडलों की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी की है, वहीं वोक्सवैगन ने कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। दरअसल ताइगुन का एंट्री-लेवल कम्फर्टलाइन ट्रिम 10.99 लाख रुपये की विशेष पेशकश कीमत पर उपलब्ध है, जो सामान्य से 70,000 रुपये कम है; यह ऑफर सीमित समय के लिए ही लागू है। ताइगुन की कीमत 20 लाख रुपये से ज्यादा है। वहीं, वर्टस की कीमत 11.56 लाख रुपये से 19.41 लाख रुपये के बीच है।

कौन भुगतेगा चुनावी गारंटी का खामियाजा

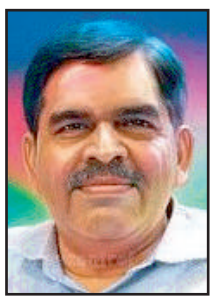

डा. अश्विनी महाजन

सबसे पहले इसका असर यह होगा कि हमारे तमाम विकासगत खर्च कम हो जाएंगे और विकास ठप हो जाएगा, जिससे भविष्य में टैक्स की प्राप्तियां भी कम हो जाएंगी। दूसरे, सरकार को भारी कर्ज लेना पड़ेगा

लोकसभा चुनावों की गर्मी चरम सीमा पर है। चुनावों में हर वोट महत्वपूर्ण है। इसलिए राजनीतिक दल हर वर्ग को लुभाने की कवायद में लगे हैं। पूर्व में राजनीतिक दल अपने चुनाव घोषणापत्र में चुनाव जीतने पर अपनी प्रस्तावित नीतियों संबंधी घोषणाएं करते रहे हैं, लेकिन पिछले लगभग डेढ़-दो दशक से राजनीतिक दल वोटरों को लुभाने के लिए मुफ्त स्कीमों संबंधी घोषणाएं करने लगे हैं। कभी किसानों के ऋण माफी की घोषणा, तो कभी युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, तो कभी सरकारी नौकरियों का वायदा आदि से शुरुआत हुई। लेकिन अब यह वादे, गारंटी का रूप ले चुके हैं। अब मुफ्त बिजली, पानी और महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की गारंटी सबसे लुभावनी मुफ्तखोरी की स्कीमें बन चुकी हैं। हालांकि कुछ स्कीमों के द्वारा जनकल्याण की भावना को समझा जा सकता है, जैसे लिंग असंतुलन को दूर करने और महिलाओं में साक्षरता और शिक्षा को बढ़ाने हेतु लाडली योजना, किसानों की हालत सुधारने के लिए सस्ते इनपुट या उनकी उपज का अधिक मूल्य देने की गारंटी आदि कुछ ऐसी जनकल्याणकारी योजनाएं हैं जिनको न्यायसंगत कहा जा सकता है। लेकिन सभी लोगों को मुफ्त बिजली, पानी या यात्रा के फलस्वरूप सरकारों के बजट बिगड़ सकते हैं या सरकारों पर कर्ज बढ़ सकता है। गारंटियों के संदर्भ में हर राजनीतिक दल दूसरे से बढ़-चढ़कर घोषणाएं कर रहा है। लेकिन वोटरों को लुभाने और येन केन प्रकारेण सत्ता हासिल करने की कवायद में देश के कई राज्य पहले से ही लगातार कर्ज के बोझ में दबते जा रहे हैं और इस कारण जहां वे एक ओर तो अपने वायदे पूरी तरह निभा पाने में असफल हो रहे हैं, साथ ही उन राज्यों का विकास कार्य तथा आवश्यक सरकारी कामकाज तक प्रभावित हो रहे हैं।

अनेक राज्य हुं प्रभावित : पंजाब में चुनावों के दौरान आम आदमी पार्टी ने मुफ्त बिजली समेत कई घोषणाएं की।

आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद इनमें से कुछ घोषणाओं पर अमल हुआ, लेकिन आज स्थिति यह है कि सरकार पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ तो रहा ही है, उससे भी ज्यादा कर्ज लेने की कवायद चल रही है और केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो राज्य को पैसा नहीं दे रही। जबकि वास्तविकता यह है कि राज्य सरकारें वोट बटोरने की कवायद में गैर जिम्मेदारी से मुफ्तखोरी की स्कीमें चला रही हैं। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, पश्चिम

बंगाल, बिहार, झारखंड आदि में लगातार कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। उधर केंद्र सरकार राज्यों को और अधिक कर्ज लेने देने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि यह 'एफआरबीएम अधिनियम' के खिलाफ है। जिन राज्यों पर मुफ्तखोरी की स्कीमों के कारण कर्ज बढ़ रहा है, वे अपने-अपने राज्य में आवश्यक खर्च करने में सक्षम नहीं हैं। पंजाब में उद्योगों को बिजली इसलिए महंगी मिल रही है क्योंकि पंजाब सरकार लगभग 60 लाख लोगों को मुफ्त बिजली दे रही है। पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। लंबे समय से विभिन्न सरकारों द्वारा दी जा रही मुफ्तखोरी स्कीमों के चलते पंजाब, जो एक समय देश का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य था, वह 19वें स्थान पर खिसक चुका है। लगभग इसी प्रकार के हालात कर्ज में डूबे अन्य राज्यों में भी हैं। 2024 के आम चुनावों में अब तो बात हर साल प्रत्येक लाभार्थी परिवार को एक लाख रुपए देने तक आ गई है। अगर ऐसी पार्टी सत्ता में आती है तो ऐसी योजना का क्रियान्वयन भयावह हो सकता है। गौरतलब है कि 31 मार्च 2023 तक भारत में सरकारों (केंद्र और राज्य) पर कुल कर्ज (उनके द्वारा दी गई गारंटी सहित) 231.7 लाख करोड़ रुपए था, जो मौजूदा कीमतों पर जीडीपी का 85.1 प्रतिशत था। इसमें से केंद्र सरकार का कुल कर्ज जीडीपी के 57.1 प्रतिशत के बराबर है और बाकी राज्य सरकारों (जीडीपी का लगभग 28 प्रतिशत) का है। हमें यह जानना होगा कि राज्य सरकारों के कर्ज का अनुपात पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ रहा है। राज्य सरकारों की गैरजिम्मेदाराना मुफ्तखोरी, सरकारों के समग्र ऋण में वृद्धि के कारण देश को परेशान कर रही है, और समग्र ऋण में यह वृद्धि के कारण अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा रेटिंग घटाने का कारण बन रही है।

क्या गारंटियां राजकोष के संकट को बढ़ा सकती हैं : समझना होगा कि केंद्र सरकार हो अथवा राज्य सरकारें, किसी भी सरकार के पास खर्च करने हेतु असीमित राजकोष नहीं होता। राजकोष मोटे तौर पर देश के लोगों की कर देने की क्षमता पर निर्भर करता है। लंबे समय से हमारा कर-जीडीपी अनुपात 17 प्रतिशत पर बना हुआ है, जिसमें से केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए करों का अनुपात जीडीपी के लगभग 10 प्रतिशत के आसपास बना हुआ है। वर्ष 2024-25 में करों की कुल प्राप्ति (निवल) का अनुमान मात्र 26.02 लाख करोड़ रुपए आंका गया है। ऐसे में कुल बजट, जो 47.66 लाख करोड़ रुपए का है, में 26.02 लाख करोड़ रुपए की कर प्राप्तियों और 4 लाख करोड़ रुपए की गैर कर राजस्व प्राप्तियों के बाद शेष राजकोषीय घाटा, जो लगभग 16.85 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें से अधिकांश पैसा उधार से प्राप्त होगा। यानी ज्यादा खर्च करने के लिए उधार के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा यह भी समझना होगा कि अर्थशास्त्रियों का इस बारे में मतैक्य है कि कुल बजट के 75 प्रतिशत से अधिक का खर्च पूर्व निर्धारित मदों पर हो जाता है, जिसमें पूर्व में लिए गए ऋणों के मूल और ब्याज की अदायगी, वेतन और पेंशन, प्रतिरक्षा खर्च, कानून और व्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय संबंध, रखरखाव समेत अन्य जरूरी खर्च शामिल हैं। इसके बाद जो बचता है, उसे इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्याणकारी योजनाओं, जैसे गरीबों के लिए घर, सार्वजनिक वितरण, मनरेगा, पेयजल, अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला, बाल विकास कार्यक्रम, कृषि विकास, औद्योगिक विकास, अल्पसंख्यक आदि के कल्याण के लिए खर्च किया जाता है। जाहिर है कि यदि कांग्रेस द्वारा हाल ही में दी गई हर गरीब परिवार की चिन्हित महिला को 1 लाख रुपए देने की गारंटी को यदि लागू करना पड़ा तो उसका असर यह होगा कि कम से कम 10-12 लाख करोड़ रुपए उसके लिए उपलब्ध कराना होगा। ऐसे में उसका क्या असर होगा, यह समझा जा सकता है। पहला, सीमित कराधान के चलते, अपने निश्चित बजट में सबसे पहली कटौती पूंजीगत व्यय की होगी। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक विकास, कृषि विकास और अन्य पूंजीगत व्यय को कम किया जाएगा। यदि इतिहास में देखें तो यूपीए के 10 सालों में कुल पूंजीगत व्यय वर्ष 2003-04 में 1.09 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2013-14 तक 1.88 लाख करोड़ रुपए तक ही पहुंचा, यानी 72 प्रतिशत की वृद्धि। जबकि एनडीए यानी नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में यह 2023-24 तक 10.01 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, यानी 433 प्रतिशत की वृद्धि। समझा जा सकता है कि यदि एक लाख रुपए प्रति वर्ष चिन्हित परिवारों को देना लागू किया गया तो पुनः हमें पूंजीगत खर्च में कटौती करनी पड़ेगी।

सबसे पहले इसका असर यह होगा कि हमारे तमाम विकासगत खर्च कम हो जाएंगे और विकास ठप्प हो जाएगा, जिससे भविष्य में टैक्स की प्राप्तियां भी कम हो जाएंगी। दूसरे, गारंटी को लागू करने के लिए सरकार को भारी कर्ज लेना पड़ेगा, जिसका असर यह होगा कि भविष्य में ब्याज की अदायगी बढ़ेगी और भविष्य का बजट भी बिगड़ेगा। तीसरे, घाटे के बजट बनाने होंगे, एफआरबीएम को तिलांजलि देनी पड़ेगी और महंगाई बढ़ेगी। चौथे, गरीबों के लिए घर, शौचालय, पेयजल आदि कार्यक्रम भी प्रभावित होंगे। पांचवें, सरकार पर कर्ज बढ़ने से रेटिंग एजेंसियां भारत की रेटिंग को कम करेंगी जिसका असर हमारे भविष्य में विदेशी निवेश, ब्याज दर आदि पर पड़ेगा, जिससे हमारा विकास ठप्प हो सकता है।

संपादक की कलम से

त्रासद क्यों हों चुनाव?

आज आम चुनाव, 2024 का जनादेश सार्वजनिक होगा। उसी के साथ चुनाव की मौजूदा प्रक्रिया सम्पन्न हो जाएगी। देश को नई लोकसभा और नई सरकार मिलेगी। निर्वाचन आयोग ने देश के मतदाताओं, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों, चुनाव कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों और मीडिया आदि का, एक विज्ञापन के जरिए, 'धन्यवाद' किया है, लेकिन कुछ खट्टे, कड़वे अनुभव, कुछ सवाल और त्रासदियां पीछे छूट गई हैं, जिनका अब जिक्र तक नहीं होगा। एक आंकड़ा '25' हमेशा त्रासदी को याद दिलाता रहेगा, क्योंकि यह संख्या उप्र और बिहार के उन चुनाव कर्मियों की है, जो भीषण लू की चपेट में आकर अपनी जिंदगी गंवा बैठे। ये त्रासदियां और भी संत्रस्त करेंगी, क्योंकि इन त्रासदियों का पूर्वानुमान होना चाहिए था। अप्रैल की शुरुआत से ही मौसम विभाग ने चेतावनी और परामर्श जारी किए थे कि इस बार गर्मी कुछ अधिक 'असामान्य' होगी। ऐसी गरम लू चलने की संभावनाएं जताई गई थीं कि लू की अवधि 10-20 दिन भी हो सकती है। अमूमन लू की अवधि 4-8 दिन की होती है। बेशक चुनाव आयोग ने मतदाताओं और चुनाव कर्मियों के बचाव के लिए, बूथ स्तर पर ही, बंदोबस्त सुनिश्चित किए थे, लेकिन चुनाव कर्मी हमेशा ही असुरक्षित तथा अति संवेदनशील महसूस करते हैं, क्योंकि उनका काम ऐसा ही है। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि चुनाव कर्मी सैनिकों की तरह खतरनाक और जोखिम भरे काम के लिए नहीं हैं।

चुनाव का दायित्व अधिकतर अध्यापक, दफ्तरी या क्लर्क आदि ही निभाते हैं, लिहाजा यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि उन्हें सुरक्षित माहौल में रखे। कमोबेश जिंदगी खत्म नहीं होनी चाहिए। इस संदर्भ में आयोग को चुनाव के वैकल्पिक कलैंडर पर विचार करना चाहिए। चुनाव आयोग की निष्पक्षता, ईमानदारी, तटस्थता और व्यापकता पर कोई सवाल या संदेह नहीं है। सर्वोच्च अदालत के सामने भी मामला गया था, जिसने हस्तक्षेप या आयोग का आधार बड़ा करने का कोई फैसला सुनाने से इंकार कर दिया। चुनाव आयोग कई चरणों में मतदान के कार्यक्रम पर पुनर्विचार जरूर करे। लोकसभा का कार्यकाल मई-जून तक है, तो चुनाव अप्रैल तक सम्पन्न कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग के पास बजट और श्रम-बल की कोई कमी नहीं है। विभिन्न सुरक्षा बलों की व्यवस्था गृह मंत्रालय करता है। यदि मतदान कम समय में ज्यादा क्षेत्रों में होना है, तो मंत्रालय उसकी भी व्यवस्था कर सकता है। कई बच्चों की परीक्षाएं आड़े आती हैं। वे भी साथ-साथ चल सकती हैं, क्योंकि सभी बच्चे मतदाता नहीं हैं। इस पहलू पर स्कूलों के साथ बैठकर तय किया जा सकता है। अब हम इतने तकनीक सम्पन्न भी हो चुके हैं कि कम अवधि में ज्यादा बड़ा चुनाव सम्पन्न करा सकते हैं। अगले संसदीय चुनाव तक ईवीएम का भी पर्याप्त बंदोबस्त किया जा सकता है। चूंकि जलवायु-परिवर्तन के कारण मौसम भी बदल रहा है।

हमने पहली बार देखा कि तापमान 50-52 डिग्री सेल्सियस तक उछल गया था। गर्मी-लू से देश भर में करीब 60 मौतें हो चुकी हैं। मतदान भी प्रभावित हुए थे। क्या मतदान 4-5 चरण में नहीं कराए जा सकते? क्या पहले ऐसा नहीं किया गया था? कमोबेश गर्मियों के 'चरम' की स्थिति में चुनाव नहीं होने चाहिए। सात चरण के मतदान का निर्णय सवालिया लगता है, बेशक आयोग कुछ भी दलीलें देता रहे। जलवायु-परिवर्तन भविष्य में व्यवस्था को और बिगाड़ सकता है। अभी तो शुरुआत है और उसे विश्व नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। कार्बन-उत्सर्जन की मात्रा थोड़ी-बहुत कम हुई है, लेकिन दूसरी भी विसंगतियां हैं। जब सरकारें राजनीतिक हित के मद्देनजर अग्रिम चुनावों की अनुशंसा कर सकती हैं, तो चुनाव आयोग संवैधानिक निकाय है। संविधान ने उसे कई विशेषाधिकार दिए हैं। देश के 23 राज्यों में 'हीट एक्शन प्लान' लागू हैं। पहला सवाल तो यही है कि सभी राज्यों में इसे लागू क्यों नहीं किया गया? मौसम के जानलेवा खतरों और जोखिमों से आम आदमी को बचाना सरकार का ही दायित्व है। सरकार चाहे, तो चुनाव आयोग के साथ मिल कर नए कलैंडर पर विचार कर सकती है। राज्यों में गर्मी को लेकर योजनाएं तो बनी हैं, लेकिन लागू करने में कुव्यवस्था है।

राय

सेर पर अब सवा सेर

हम जिसे सामान्य मानते या जिस आंख से सियासत को देखते हैं, उससे कहीं अलग देश के ढर्रे में लोकतंत्र का समाधान है। पहली जून को हिमाचल में छह उपचुनाव की कलाबाजियां, मतदान से पूरी हुईं तो अब बिसात पर तीन निर्दलीय विधायक रख दिए गए। बहुप्रतीक्षित लोकतांत्रिक फैसले की वैधता तीन जून को पूरी हो गई जब विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने तीन निर्दलीयों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए, यानी लोकसभा परिणामों की आहट में हिमाचल की गलियों में पुनः उपचुनाव की फुसफुसाहट शुरू हो गई। पहले ही तीन निर्दलीयों द्वारा इस्तीफा देना ऐसा आकस्मिक प्रहार था जो प्रदेश के सत्ता पक्ष से बहुत कुछ छीन गया, लेकिन अब इनका मंजूर होना 'सेर पर सवा सेर' होना है, यानी 'तू डाल-डाल, तो मैं पात-पात' जैसा फैसला आगे की सियासत को रगड़ा लगा रहा है। आज फैसले का बड़ा दिन है और ऊंट की हर करवट पर परेशानी का सबब बन सकता है, लेकिन तीन निर्दलीयों की विदाई से विधानसभा गिनती में रिक्तियां सारा खेल बदल सकती हैं। बहरहाल देहरा से होशियार सिंह, हमीरपुर से आशीष शर्मा और नालागढ़ से केएल ठाकुर के विधानसभा से रुखसत होने से प्रदेश की हवाओं में सियासत का नमक फिर हलाल होने के लिए जनता की अदालत में जाएगा। व्यावहारिक रूप से चुनाव परिणामों के बावजूद विधानसभा 65 प्रतिनिधियों की रह जाएगी तथा बहुमत के लिए कांग्रेस को मात्र 33 विधायक चाहिएं। यह कोई अपूर्णीय क्षति नहीं हो सकती और आसानी से सुक्खू सरकार का टिकाऊ अंकगणित प्रभावी हो जाएगा। शुक्र यह कि विधायक डिसक्वालीफाई नहीं हुए, वरना चाल, चरित्र और चेहरे पर कई विराम लग जाते। यह दीगर है कि अब कसरतें पुनः देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ में सत्ता के संघर्ष को कठिन दौर में पहुंचाएंगी। जाहिर है लोकतंत्र कहीं न कहीं बंधक तो जरूर बन रहा है, वरना छह उपचुनाव न होते और अगर होने ही थे तो पूरे के पूरे नौ हो जाते, लेकिन 'बिजलियां तूफानों की हकीकत में रोशनी नहीं होतीं, यह तो दस्तूर है तेरे आंगन में खबर देने का।' हिमाचल में जनादेश के सारे पहलू गड्ड मड्ड से हैं। जो सवा साल पहले सोचा गया, वह आदेश बदल गया। आज के चुनाव परिणाम राजनीति को उसकी हैसियत और नेताओं को उनकी औकात बताएंगे। हिमाचल में लोकसभा की चार सीटों के परिणाम से भी गहरे असर में छह उपचुनाव कहे और सुने जाएंगे। आज चुनाव की कुछ आहुतियां पूर्ण होंगी, लेकिन पूर्णाहुति का मंत्र अभी फूंका जाएगा। प्रदेश की राजनीतिक उथल-पुथल में गोटियां भी कैसी-कैसी कि छह विधायक आज अपना रिपोर्ट बताएंगे, जबकि सिफर कर दिए गए तीन विधायक अब केवल भाजपा के लाल कहलाएंगे। एक और चुनाव के लिए तीन विधानसभा क्षेत्रों के गले में घंटियां तब तक बजती रहेंगी, जब तक उपचुनावों की नई पारी नहीं सजती। बहरहाल, अध्यक्ष के फैसले ने गिल्लियां उड़ाई जरूर, लेकिन मैच अभी जारी है। काफी कुछ आज आने वाले लोकसभा तथा विधानसभा के उपचुनावों से सामने आएगा। फिलहाल कहीं कोई खतरा नहीं, लेकिन सियासत के माध्यम से प्रदेश का और कितना चीरहरण हो सकता है, इसके ऊपर कोई रोक नहीं। पिछले कुछ समय से और निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे मंजूर होने तक जो भी घटा है, वह सामान्य राजनीति नहीं है। भले ही कोई जीते या कोई हारे, लेकिन सियासत ने जनादेश को पलटने या शर्मिंदा करने की राहें यहां भी पहुंचा दी हैं। कुछ आशा आज के चुनाव परिणाम दे पाए, तो आइंदा कोई ऐसी जुर्रत नहीं करेगा, फिर भी सियासत के सींग नहीं होते, लेकिन घायल सबसे अधिक यही करती है। देखें जनता को राजनीति अपनी तरह दिखा पाती है या मतदाता दिन में तारे दिखाने का अपना सामथ्र्य पेश करते हैं।

बढ़ते एनपीए की समस्या का समाधान जरूरी

उधार देने से पहले उधार लेने वाली पार्टियों की पिछली पृष्ठभूमि और अन्य वास्तविकताओं का पता लगाना जरूरी है। एक अच्छी सूचना प्रबंधन प्रणाली से किसी परियोजना के प्रारंभिक चेतावनी संकेत का पता लगाया जा सकता है। तनाव ग्रस्त परिसंपत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए पुनर्निर्माण कंपनियों की स्थापना हो'

भारत की बैंकिंग प्रणाली लंबे समय से एनपीए की समस्या से ग्रस्त है। इससे बैंकों की पूंजी पर्याप्तता के साथ-साथ लाभ पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। सरकार सार्वजनिक बैंकों में अपनी पूंजी लगाकर क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ावा दे रही है। एनपीए की राशि इस समय 7 लाख करोड़ है जो चिंता का विषय है, क्योंकि यह राशि किसी भी काम की नहीं है। बैंकों का एनपीए दो स्थितियों में बढ़ता है। एक जब अर्थव्यवस्था में कारोबार सुस्त रहता है। दूसरा जब कोई व्यक्ति या कंपनी जानबूझ कर बैंकों का कर्ज नहीं चुकाता है। इन्हें विल्फुल डिफाल्टर कहते हैं। केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री ने लोकसभा में बताया कि 31 मार्च 2023 को भारत में 2623 इरादतन चूककर्ता हैं। इन उधारकर्ताओं ने 196049 करोड़ रुपए भारतीय बैंकों के देने हैं। विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी ने भारतीय बैंकों को 22000 करोड़ रुपए से अधिक का चूना लगाया और देश छोड़कर भाग गए। आरबीआई के अनुसार बैंकों ने 2012-13 से अब तक 15 लाख करोड़ रुपए के ऋण राइट ऑफ किए हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में सार्वजनिक एवं निजी बैंकों ने 172800 करोड़ रुपए राइट ऑफ किए, जो कि तीन महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों मनरेगा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य में से किसी एक को 2023-24 के बजट में आबंटित राशि से कहीं ज्यादा था। इसमें से बहुत बड़ा हिस्सा कॉरपोरेट जगत की फर्मों को प्रदान किया गया है। खुदरा उधार कर्ताओं द्वारा किए डिफॉल्ट बहुत ही कम हैं।

एनपीए की सकल राशि भारत सरकार के एक साल के आम बजट की एक-तिहाई के बराबर है। एनडीए सरकार ने सार्वजनिक बैंकों को पुनःपूंजीकरण के लिए 2.76 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार बैंक को जब किसी परिसंपत्ति (असेट्स) से आय अर्जित होना बंद हो जाती है, तो उसे एनपीए मान लिया जाता है। अगर व्यक्ति लगातार 3 महीने तक मासिक किस्तों का भुगतान नहीं कर पाता तो बैंक को अपने बही-खाते में यह राशि एनपीए के रूप में दर्ज करनी होगी। इस तरह 90 दिन तक मूलधन या ब्याज की किस्त का भुगतान न होने पर लोन खाता एनपीए बन जाता है। एनपीए का मतलब यह नहीं कि बैंक की रकम डूब गई है या बैंक ने इसे वसूलना छोड़ दिया है। लोन को राइट ऑफ करने के बाद भी बैंकों को विभिन्न तरीकों द्वारा रिकवरी करनी पड़ती

है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार बैंकों ने 109186 करोड़ रुपए (18.6 प्रतिशत) कुल राइट ऑफ राशि, जो 586891 करोड़ रुपए थी, से पिछले 3 वर्षों मे रिकवर किया है। 2000 के दशक की शुरुआत में भारत की अर्थव्यवस्था फल-फूल रही थी, जिसके कारण बैंकों ने व्यापारियों और कंपनियों को काफी मात्रा में ऋण प्रदान किए। हालांकि यह कंपनियां अपना काम अच्छा नहीं कर पा रही थीं और अपना कर्ज भी नहीं चुका पा रही थी। एनपीए यूपीए सरकार की नीतियों से बढ़ा क्योंकि उस समय ज्यादा से ज्यादा ऋण दिए गए। एवरग्रीनिंग ऋण देना, यह एक ऐसी प्रेक्टिस थी जिसमें उधार लेने वालों को और अधिक उधार दिया जाता है, चाहे उसने ऋण की अदायगी बंद भी कर दी है, ताकि ऋण बही-खाते में दिया हुआ दर्शाया जा सके।

गैर निष्पादित परिसंपत्तियां बैंकों के कामकाज पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। यही बैंकों के पतन का कारण है। जब एनपीए बढ़ता है तो बैंकों को ज्यादा कर्ज लेना पड़ता है। इससे उनकी फंड जुटाने की लागत बढ़ती है जिसका बोझ ग्राहकों पर ऊंची ब्याज दरों के रूप में पड़ता है। जब कर्ज फंस जाता है तो उसकी प्रोविजनिंग के लिए मुनाफे से एक निश्चित राशि अलग रखनी होती है। मुनाफा कम होने पर बैंकों के विस्तार और ग्राहक सेवाओं पर असर होता है। एनपीए बैंक की वित्तीय अवस्था को मापने का पैमाना है। यह अर्थव्यवस्था पर बोझ होता है। बैड लोन से बैंकों के लाभांश में कमी आती है जिससे बैंकों के लिए ऋण देना मुश्किल हो जाता है और निवेश में कमी आने लगती है। अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। एनपीए को पूरी तरह से खत्म करना संभव नहीं है, परंतु संरचनात्मक सुधार करके निश्चित रूप से सुधार लाया जा सकता है, जैसे बैंकों में व्याप्त अंदरूनी तथा अन्य खामियों का इलाज, बैंकों के कार्यों में राजनीतिक हस्तक्षेप पर रोक, मानव संसाधन में बढ़ोतरी, वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही निर्धारित करना, उचित प्रशासन, सरकार द्वारा बैंकों को अधिक अधिकार देना, वरिष्ठ कर्मचारियों को आवश्यक ट्रेनिंग देना, शीर्ष अधिकारियों की नियुक्ति और व्यवस्था में बदलाव, कार्यकारी निदेशकों/बोर्ड के सदस्यों/अध्यक्षों तक बदलाव हो, ताकि शीर्ष प्रबंधन की गुणवत्ता बढ़ाई जा सके।

कुछ शाखा प्रबंधक या अधिकारी जिनका कैरियर ज्यादातर शाखा स्तर पर ही आधारित होता है, वे बगैर किसी विशिष्ट जांच-पड़ताल के बड़े ऋण पास कर देते हैं, चाहे वे ईमानदारी से किए हैं, लेकिन आवश्यक कौशल के अभाव से ऋण एनपीए में परिवर्तित होने से नहीं रोका जा सकता है। इसलिए इन शाखा प्रबंधकों को प्रत्येक स्तर पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। एनपीए मामलों में जल्दी कार्रवाई की जानी चाहिए। रिजर्व बैंक को सशक्त मानव संसाधन नियुक्त करके निरीक्षण व्यवस्था में सुधार लाना चाहिए। वित्तीय लेनदेन में आर्टिफिशियल इंटैलिजैंस द्वारा नजर रखने से वित्तीय धोखे कम किए जा सकते हैं। उधार देने से पहले उधार लेने वाली पार्टियों की पिछली पृष्ठभूमि और अन्य वास्तविकताओं का पता लगाना जरूरी है। एक अच्छी सूचना प्रबंधन प्रणाली से किसी परियोजना के प्रारंभिक चेतावनी संकेत का पता लगाया जा सकता है। तनाव ग्रस्त परिसंपत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए पुनर्निर्माण कंपनियों की स्थापना की जानी चाहिए। इरादतन चूककर्ताओं से निपटने के लिए 2002 का सरफेसी अधिनियम, 2013 का कंपनी अधिनियम, 2017 का बैंकिंग अधिनियम और भारतीय दंड संहिता 1860 के नियमन हैं, परंतु बढ़ती हुई एनपीए की वारदातों से लगता है ये नियमन काफी नहीं हैं, इनको और कड़े करने की आवश्यकता है।

सत्यपाल वशिष्ठ

पीए सिद्धार्थ

मीडियाटेशन

भारतीय मूल की विख्यात साहित्यकार झुम्पा लाहिड़ी अपने एक उपन्यास में कहती हैं कि अगर कोई व्यक्ति तीन पीढ़ियों से एक ही जगह पर रहता आ रहा हो, तो उसका दिमाग आलू जैसा हो जाता है। मुझे उनकी इस उक्ति से सामंजस्य बिठाने में उस समय दिक्कत हो जाती है, जब मैं किसी ऐसे आदमी को देखता हूं जो सालों से यह दावा करता आ रहा हो कि उसने बचपन में चाय बेची थी, घर छोड़ दिया था और सालों हिमालय में तपस्या की। इतना ही नहीं, वह हर स्थान तथा व्यक्ति से नाता जोडने में उसी तरह माहिर हो, जैसे एक कांगड़ी कहावत है, 'जो ननंद का ननंदोई, वह मेरा भी टम्मकटोई।' जाहिर है ऐसा आदमी कभी भी तीन पीढ़ियों से एक जगह पर नहीं रहा होगा। पर झुम्पा लाहिड़ी तीन पीढ़ियों पर आकर रुक गईं। सात पीढ़ियों तक नहीं पहुंची। अगर पहुंचती तो ऐसे आदमी से मिलने पर वह उसे आलू नहीं, रोड़ा या गिट्टी कहतीं। तीन पीढ़ियों से एक ही जगह पर रहने से आदमी के आलू हो जाने की तरह छद्म आध्यात्मिकता के रंग में रंगा आर्यावर्त आज तक अपना बचकानापन छोडने में आलू ही सिद्ध हुआ है। हालांकि समय-समय पर बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, नानक या कबीर जैसे सिद्धों ने प्रयास अवश्य किए हैं। पर इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए आदिकाल से ही हिरण्यकश्यप, रावण, कालनेमि, मारीच, कंस, कृपालु महराज, राम रहीम, आसाराम जैसे लोग हर युग में धर्म और ध्यान के नाम पर लोगों को ठगते आ रहे हैं। 'मेडिटेशन' शब्द फ्रेंच भाषा के 'मेडिटैसिओन' और लैटिन के 'मेडिटेटियो' की एक क्रिया मेडिटरी से लिया गया है।

अंग्रेजी में मेडिटेशन का अर्थ है 'सोचना, विचार करना या योजना बनाना।' हिंदू और बौद्ध धर्म का ध्यान संस्कृत मूल के ध्याई से आया है, जिसका अर्थ चिंतन या ध्यान करना है। पर केदारनाथ और कन्याकुमारी के प्रथमाक्षर 'क' होने पर कई बार मुझे लगता है कि इन चुनावों में 'म' का सहारा किसी विशेष प्रयोजन से लिया गया है। हर रोज अठारह-अठारह घंटे काम करने वाले फैशनवीर कैमराजीवी को किसी तांत्रिक ने बताया होगा कि विपक्ष के मेनिफेस्टो से मुकाबला करने के लिए आप 'म' शब्द को बार-बार दोहराएं और आपातकाल में 'म' के पूर्ववर्ती अक्षर 'भ' का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए 'म' से निकला मंगलसूत्र, मछली, मटन, मजहब, मुसलमान और मुजरे तक पहुंचने के बाद 'भ' से निकले भैंस तक जा पहुंचा। तांत्रिक के 'म' के टोटके से इस बार केदारनाथ का ध्यान 'मेडिटेशन' में बदल गया। पर मेडिटेशन में बैठते समय अगर कान में एक भी मच्छर भिनभिना जाए तो क्रांतिवीर फिल्म के नायक नाना पाटेकर के शब्दों में एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है।

इसके बावजूद दस कैमरों और तीन हजार जवानों से घिरे अवतारी सभी चैनलों पर ध्यान का अभिनय करते दिखे। 'लाईट, कैमरा, एक्शन' के बाद आंखों पर चश्मा लगाए अवतारी का मेडिटेशन शुरू हुआ। पर मेरा अनुभव है कि दस दिशाओं में टंके दस कैमरे जब रील बना रहे हों तो मेडिटेशन का 'मीडियाटेशन' में बदलना स्वाभाविक है। हो सकता है कि मीडियाटेशन के समय आंखों पर चश्मा पहनने से दृश्य, दर्शक और दृष्टा का भेद समाप्त हो जाता हो या फिर ऐनक के शीशे में अनुभव स्पष्ट नजर आते हों। पर मुझे अभी तक यह समझ में नहीं आया कि मीडियाटेशन में विश्व गुरू घंटाल एक आंख खुली क्यों रखते हैं? हो सकता है कि मीडियाटेशन में यह देखना जरूरी हो कि सभी कैमरे काम कर रहे हैं या नहीं। या हो सकता है कि सामने लगी स्क्रीन में अवतारी पुरुष अपने को देखने का मोह न छोड़ पाए हों। पर नॉन-बॉयोलॉजिकल आदमी के लिए कुछ भी संभव है। तर्क को कुतर्क में बदलने से लेकर, दहाडने से मिमियाने तक और मूर्खों की तरह हंसने से लेकर रोने तक। मेडिटेशन में व्यक्तित्व संवरता है, सन्तुलित होता है और बुद्धत्व की ओर बढ़ता है, लेकिन मीडियाटेशन में अपना हित साधने वाला व्यक्ति अभिनेता से अधिक कुछ नहीं होता।

इस तारीख के बाद नहीं होगा फ्री में आधार अपडेट, हर अपडेशन के लिए इतना देना होगा चार्ज

परिवहन विशेष न्यूज

आधार कार्ड बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है। यूआईडीएआई ने आधार यूजर्स के लिए ऑनलाइन फ्री अपडेशन की सुविधा दी है। आधार कार्ड डिटेल्स को फ्री में अपडेट करवाने की आखिरी तारीख 14 जून 2024 (शुक्रवार) है। है। आधार यूजर्स केवल ऑनलाइन ही फ्री में आधार कार्ड अपडेट करवा सकते हैं। आइएयहां जानते हैं कि आधार कार्ड को ऑनलाइन अपडेट करने का प्रोसेस क्या है?

नई दिल्ली। आधार कार्ड बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है। आज के समय में कई काम के लिए आधार कार्ड की जरूरत होती है। आधार कार्ड में एक आईडी-प्रूफ के तरह काम करता है। ऐसे में कई बार हमें उसमें अपने घर का पता, मोबाइल नंबर चेंज या अपडेट करना होता है।

कई आधार यूजर्स ने 10 साल से अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं किया है। ऐसे में यूआईडीएआई (UIDAI) ने आधार यूजर्स के लिए ऑनलाइन फ्री अपडेशन की सुविधा दी है। आधार कार्ड डिटेल्स को फ्री में अपडेट करवाने की आखिरी तारीख 14 जून 2024 (शुक्रवार) है।

आधार यूजर्स केवल ऑनलाइन ही फ्री में आधार कार्ड अपडेट करवा सकते हैं।

ऑफलाइन आधार कार्ड अपडेट करने पर 50 रुपये प्रति अपडेशन फीस देनी होगी।

ये जानकारी होगी अपडेट

यूआईडीएआई के अनुसार आप अपने आधार कार्ड में घर का पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि डिटेल्स को अपडेट करवा सकते हैं। वहीं फोटो, बायोमैट्रिक, आईरिस जैसे डिटेल्स को अपडेट करवाने के लिए आधार यूजर्स को आधार केंद्र जाना होगा।

ऑनलाइन कैसे करवाएं आधार अपडेट (How to update Aadhaar online free)

आपको सबसे पहले UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट (https://uidai.gov.in/) पर जाना है।

अब आधार अपडेट सर्विस को सेलेक्ट करें।

इसके बाद आधार नंबर और ओटीपी (OTP) की मदद से लॉग इन करना है।

अब आधार अपडेट के ऑप्शन का चयन करें और जो डिटेल्स अपडेट करना है वो करें।

नई सरकार बनने से पहले डूब गए निवेशकों के 26 लाख करोड़ रुपये, 4 साल के बाद बाजार में आई इतनी बड़ी गिरावट

परिवहन विशेष न्यूज

मंगलवार को शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिले है। यह गिरावट पिछले 4 साल में सबसे ज्यादा है। आज सेंसेक्स 5 फीसदी और निफ्टी 6 फीसदी से ज्यादा गिर गए। बाजार में जारी भारी गिरावट से निवेशकों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। शेयर बाजार में आई गिरावट से निवेशकों को 26 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

नई दिल्ली। मंगलवार को शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिले है। यह गिरावट पिछले 4 साल में सबसे ज्यादा है। आज सेंसेक्स 5 फीसदी और निफ्टी 6 फीसदी से ज्यादा गिर गए। बाजार में जारी भारी गिरावट से निवेशकों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।

बाजार में आई गिरावट को लेकर जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार, डॉ. वी के विजयकुमार का कहना है कि

स्टॉक मार्केट में तेजी से गिरावट का कारण अब तक आए नतीजे है। नतीजे एग्जिट पोल से कम रहे हैं, जिसे बाजार ने कल खारिज कर दिया था। अगर बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिलता है तो निराशा होगी और इसका असर बाजार पर भी दिख रहा है।

डूब गए निवेशकों के पैसे

सोमवार को बाजार में तेजी से निवेशकों को 15 लाख करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। आज वहीं निवेशकों को नुकसान का सामना करना पड़ा रहा है। बीएसई के एम-कैप डिटेल्स के अनुसार सोमवार को बीएसई में लिस्टिड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन 4,25,91,511.54 करोड़ रुपये था।

यह एम-कैप आज गिरकर 4,00,03,834.56 करोड़ रुपये हो गया है। इसका मतलब है कि शेयर बाजार में आई गिरावट से निवेशकों को 26 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

बाजार में हाहाकार

स्टॉक मार्केट में यह गिरावट 24 FEB 2022 के बाद सबसे बड़ी है। 24 FEB 2022 को इंट्राडे में सबसे बड़ी गिरावट है। वहीं कई एक्सपर्ट के अनुसार यह कोविड के बाद की सबसे बड़ी गिरावट है।

इंडिया वीआईएक्स में तेजी

देश में चुनावी माहौल के समय इंडिया वीआईएक्स में तेजी देखने को मिलती है।

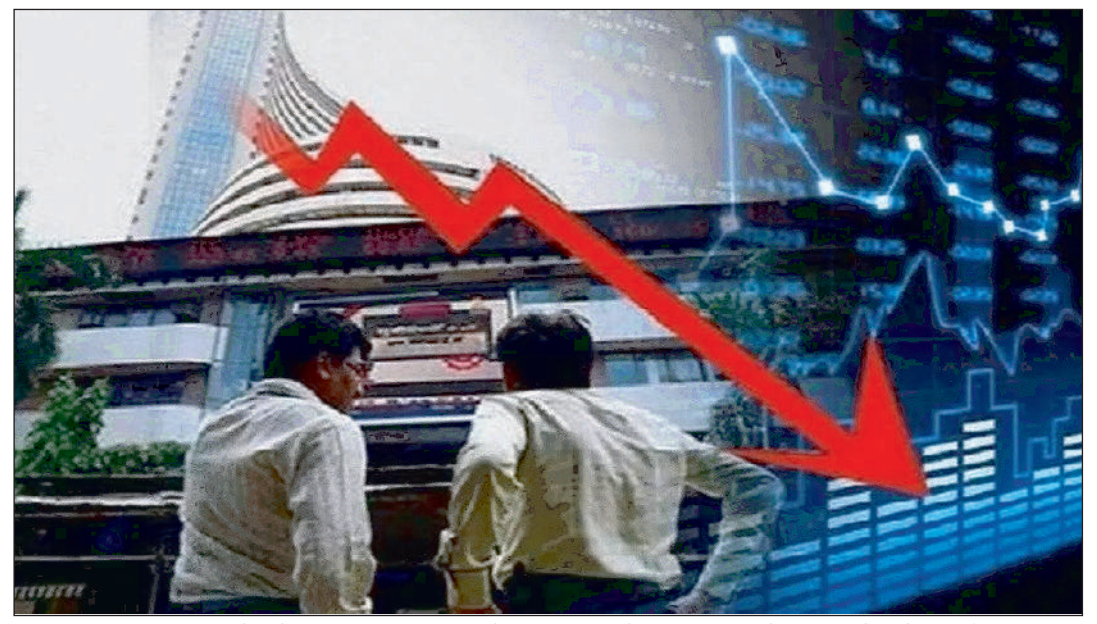

आज भी इंडिया वीआईएक्स तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। मंगलवार को इंडिया वीआईएक्स में 32 फीसदी की तेजी आई है। इंडिया वीआईएक्स में आई तेजी के बाद शेयर मार्केट के निवेशकों को आगाह रहना चाहिए।

शेयर मार्केट में हुआ उलटफेर तो कुछ देर के लिए बंद होगा कारोबार, नहीं होगी शेयर की खरीद-बिक्री

जहां एक तरफ आम जनता लोकसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार कर रही है तो वहीं ट्रेडर्स बाजार की तेजी पर नजर बनाए हुए हैं। अगर आप भी शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। दरअसल जब भी शेयर बाजार में अचानक से शानदार तेजी आती है तो निवेशकों को बचाने के स्टॉक एक्सचेंज सर्किट ब्रेकर लगाते हैं।

नई दिल्ली। जहां एक तरफ आम जनता लोकसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार कर रही है तो वहीं ट्रेडर्स बाजार की तेजी पर नजर बनाए हुए हैं। सोमवार के सत्र में सेंसेक्स और निफ्टी में शानदार तेजी देखने को मिली थी। ऐसे में जहां निवेशकों को मुनाफा हुआ था तो वहीं उन्हें नुकसान का डर भी है।

शेयर बाजार का इलेक्शन के साथ कनेक्शन है यह तो सोमवार के सत्र में पूरी तरह से साफ है। लेकिन डर है कि अगर शेयर बाजार में उलट-फेर हुआ तो निवेशकों को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। वैसे तो शेयर बाजार में उलटफेर की आशंका कम ही है, लेकिन फिर भी स्टॉक एक्सचेंज इसके लिए तैयार है।

दरअसल, निवेशकों में बाजार में तेज उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए स्टॉक एक्सचेंज सर्किट ब्रेकर (Circut Breaker) लगाता है। आज भी बाजार में यह सर्किट ब्रेकर लग सकते हैं।

क्या होता है सर्किट ब्रेकर

2 जुलाई 2001 में स्टॉक एक्सचेंज ने इंडेक्स-बेस्ड मार्केट-वाइड सर्किट ब्रेकर लागू किया था। यह ब्रेकर शेयर मार्केट के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। यब ब्रेकर 3 स्टेज में लगते हैं। स्टॉक मार्केट में 10 फीसदी, 15 फीसदी और 20 फीसदी के उतार-चढ़ाव पर यब ब्रेकर लगते हैं।

आपको बता दें कि सर्किट ब्रेकर में सभी इक्विटी और इक्विटी डेरीवेटिव मार्केट एक समयसीमा तक बंद रहते हैं। इसका मतलब है कि तय सीमा तक निवेशक शेयर की खरीद-बिक्री नहीं कर सकते हैं।

इनसाइड

नई सरकार में इंफ्रा प्रोजेक्ट पर खर्च जारी रहने की उम्मीद, बैंकिंग शेयरों ने भरी उड़ान

बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयरों में सबसे ज्यादा 11.88 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई। बीएसई में बैंक के शेयर 296.65 रुपये प्रति इकाई पर बंद हुए। इससे इतर अन्य बैंकों के शेयर भी पांच प्रतिशत से ज्यादा बढ़कर बंद हुए। सभी 12 सरकारी बैंकों में से बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरों में सबसे कम 5.07 प्रतिशत की वृद्धि रही। एसबीआई के शेयर 9.12 प्रतिशत बढ़कर बंद हुए।

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के बाद सभी एग्जिट पोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली एनडीए के लगातार तीसरी बार सत्ता में आने का अनुमान है। इससे संभावना है कि संभावित बीजेपी सरकार अपने पिछले दो कार्यकाल की तरह नीतिगत सुधारों को जारी रखेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देगी। इससे शेयर मार्केट में तूफानी तेजी दिखी। खासकर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लोन उपलब्ध कराने वाले बैंकिंग स्टॉक में ज्यादा उछाल दिखा।

सरकारी बैंकों ने भरी निवेशकों की झोली

बैंक	शेयर में वृद्धि (प्रतिशत में)
बैंक ऑफ बड़ौदा	11.88
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	11.64
एसबीआई	9.12
यूको बैंक	8.53
केनरा बैंक	8.52
इंडियन बैंक	7.16
पंजाब एंड सिंध बैंक	6.80
इंडियन ओवरसीज बैंक	6.17

चुनावी नतीजों के बाद आरबीआई लेगा अहम फैसला, बढ़ या घट सकती है आपकी ईएमआई

जून का महीना कई तरीके से जरूरी है। जहां आज यानी 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों का एलान होगा। वहीं कल से भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा बैठक शुरू होगी। इस बैठक में रेपो रेट (Repo Rate) समेत कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। अगर रेपो रेट में कटौती होती है तो इससे लोन की EMI कम हो जाती है।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। जून का महीना कई तरीके से जरूरी है। जहां आज यानी 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों का एलान होगा। वहीं कल से भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा बैठक शुरू होगी। इस बैठक में रेपो रेट (Repo Rate) समेत कई बड़े फैसले लिए जाएंगे।

आम जनता की नजर रेपो रेट में कटौती पर बनी रहती है। दरअसल, अगर रेपो रेट में कटौती होती है तो इससे लोन की EMI कम हो जाती है।

आरबीआई की एमपीसी बैठक (RBI MPC Meet) को लेकर एक्सपर्ट का कहना है कि देश में बढ़ती महंगाई के बीच आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कटौती की संभावना नहीं है। केंद्रीय बैंक ने पिछली एमपीसी बैठक में भी रेपो रेट को स्थिर रखा था।

फरवरी 2023 से केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट में बदलाव किया था। फरवरी 2023 में रेपो रेट को 6.25 फीसदी से बढ़ाकर 6.50 फीसदी कर दिया गया था।

कब होगी एनपीसी बैठक में लिए गए फैसलों की घोषणा

भारतीय रिजर्व बैंक की एमपीसी बैठक तीन दिवसीय होती है। इस बैठक की

अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) करते हैं। यह बैठक 5 जून 2024 से शुरू होगी और इस बैठक में लिए गए फैसलों का एलान 7 जून 2024 (शुक्रवार) को होगी।

अगर इस बार भी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होता है तो यह लगातार 8वीं बार होगा जब रेपो रेट को अपरिवर्तित रखने का फैसला लिया जएगा।

क्या होता है रेपो रेट? (What is Repo Rate)

केंद्रीय बैंक देश के बाकी बैंक को संचालन के लिए कर्ज देता है। यह कर्ज जिस दर पर दिया जाता है उसे ही रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट का सीधा कनेक्शन लोन (Loan) से होता है। दरअसल, केंद्र सरकार जिस दर पर बैंक को कर्ज देता है बैंक भी उसी दर पर आम जनता को लोन देती है।

अगर आरबीआई रेपो रेट में कटौती का फैसला लेता है तो फिर होम लोन (Home Loan), व्हीकल लोन (Vehicle Loan) और बाकी लोन की दरें भी कम हो जाती है।

चुनावी नतीजों के एलान से पहले जारी हुई पेट्रोल-डीजल की नई कीमतें

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 4 जून 2024 (मंगलवार) के लिए फ्यूल प्राइस अपडेट कर दिया है। आज लोकसभा चुनाव के नतीजों का एलान होने वाला है। ऐसे में गाड़ी चालक को उम्मीद है कि फ्यूल प्राइस में कटौती होगी। लोकसभा चुनाव से पहले फ्यूल प्राइस में कटौती हुई थी। आइए जानते हैं कि आज आपके शहर में फ्यूल प्राइस क्या है?

नई दिल्ली। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 4 जून 2024 (मंगलवार) के लिए फ्यूल प्राइस अपडेट कर दिया है। आज लोकसभा चुनाव के नतीजों (Loksabha Election Result 2024) का एलान होने वाला है। ऐसे में गाड़ी चालक को उम्मीद है कि फ्यूल प्राइस में कटौती होगी।

लोकसभा चुनाव से पहले तेल कंपनियों ने 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है। देश के सभी शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम अलग होते हैं। चलिए, जानते हैं कि आज आपके शहर में फ्यूल कितने रुपये लीटर मिल रहा है?

देश के महानगरों में क्या है पेट्रोल-डीजल के दाम

HPCL की वेबसाइट के

अनुसार देश के महानगरों में ये है फ्यूल की कीमतः

देश की राजधानी दिल्ली में प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत 94.76 रुपये और प्रति लीटर डीजल की कीमत 87.66 रुपये है।

आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली मुंबई में एक लीटर पेट्रोल 104.19 रुपये और प्रति लीटर डीजल 92.13 रुपये मिल रहा है।

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में पेट्रोल प्राइस 103.93 रुपये प्रति लीटर और डीजल 90.74 रुपये प्रति लीटर है।

चेन्नई में पेट्रोल 100.73 रुपये प्रति लीटर और डीजल 92.32 रुपये प्रति लीटर पर मिल रहा है।

मेट्रोसिटी कहे जाने बेंगलुरु में पेट्रोल 99.82 रुपये और डीजल 85.92 रुपये प्रति लीटर है।

महंगाई लेकर आएगी गर्मी: कामकाजी घंटों में आई कमी और उत्पादन लागत में भी हुआ इजाफा

परिवहन विशेष न्यूज

मार्च में सूचकांक 16 वर्ष के उच्चतम स्तर 59.1 पर पहुंच गया था। पीएमआई के तहत 50 से ऊपर सूचकांक होने का मतलब उत्पादन गतिविधियों में विस्तार है जबकि 50 से नीचे का आंकड़ा गिरावट को दर्शाता है। एचएसबीसी की वैश्विक अर्थशास्त्री मैत्रेयी दास ने कहा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मई में विस्तार के दायरे में रहा हालांकि इसकी गति धीमी रही जिसका कारण नए ठेकों और उत्पादन में मंदी रही।

नई दिल्ली। भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मई में लगातार दूसरे महीने वृद्धि दर धीमी रही। हालांकि वैश्विक बिक्री में 13 वर्षों में सर्वाधिक वृद्धि के साथ यह क्षेत्र विस्तार की स्थिति में बना रहा। मौसमी रूप से समायोजित 'एचएसबीसी इंडिया विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक' (पीएमआई) मई में घटकर 57.5 हो गया जो अप्रैल में 58.8 था।

मार्च में सूचकांक 16 वर्ष के उच्चतम स्तर 59.1 पर पहुंच गया था। पीएमआई के तहत 50 से ऊपर सूचकांक होने का मतलब उत्पादन गतिविधियों में विस्तार है जबकि 50 से नीचे का आंकड़ा गिरावट को दर्शाता है। एचएसबीसी की वैश्विक अर्थशास्त्री मैत्रेयी दास ने कहा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मई में विस्तार के दायरे में रहा, हालांकि इसकी गति धीमी रही जिसका कारण नए ठेकों और उत्पादन में मंदी रही।'

दास ने कहा कि मंदी का कारण भीषण गर्मी के बीच

कामकाजी घंटों में कमी और उत्पादन लागत में वृद्धि बताया जा रहा है। सर्वे के अनुसार, प्रतिस्पर्धा और चुनाव संबंधी व्यवधानों के कारण वृद्धि अवरुद्ध हुई है। कुल बिक्री के रुझान के विपरीत मई में नए निर्यात ठेकों में तीव्र गति से वृद्धि हुई है।

अंतरराष्ट्रीय बिक्री में यह उछाल 13 वर्षों में सबसे अधिक रहा, क्योंकि मैन्यूफैक्चरर्स को अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, यूरोप और पश्चिम एशिया के कई देशों में ग्राहकों से लाभ प्राप्त हुआ है। साथ ही मार्च 2005 में आंकड़ा संग्रहण शुरू होने के बाद से मैन्यूफैक्च¨रग सेक्टर में रोजगार में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई।

अदाणी समूह की कंपनियों के शेयरों में जोरदार खरीदारी, 19.42 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचा मार्केट कैप

इसमें अदाणी एंटरप्राइजेज अदाणी पो र्ट्स अदाणी पावर और अदाणी ग्रीन प्रमुख हैं। इस तेजी के साथ समूह की 10 सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण बढ़कर 19.42 लाख करोड़ रुपये हो गया है। अमेरिका की ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की ओर से खरीदारी की सलाह के बाद बीते शुक्रवार को समूह की कंपनियों के शेयरों में 14 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई थी।

नई दिल्ली। भाजपा के तीसरी बार सत्ता में आने के संकेतों के बीच अदाणी समूह की कंपनियों के शेयरों में जमकर खरीदारी हो रही है। सोमवार को समूह की कई कंपनियों के शेयर रिकार्ड उच्च स्तर तक पहुंचे। समूह की कंपनी अदाणी पावर के शेयरों में सबसे ज्यादा करीब 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

समूह की अधिकांश कंपनियों के शेयर हिंडनबर्ग रिसर्च से पहले के स्तर पर पहुंच गए हैं। इसमें अदाणी एंटरप्राइजेज, अदाणी पोर्ट्स, अदाणी पावर और अदाणी ग्रीन प्रमुख हैं। इस तेजी के साथ समूह की 10 सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण बढ़कर 19.42 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

अमेरिका की ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की ओर से खरीदारी की सलाह के बाद बीते शुक्रवार को समूह की कंपनियों के शेयरों में 14 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई थी। जेफरीज ने अगले एक दशक में समूह की ओर से 90 अरब डॉलर के पूंजीगत खर्च को देखते हुए खरीदारी की सलाह दी है।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान समूह की कंपनियों का कर-पूर्व लाभ 45 प्रतिशत बढ़कर 82,917 करोड़ रुपये या करीब 10 अरब डॉलर रहा है।

कंपनीवार शेयर मूल्य और पूंजीकरण

अदाणी एंटरप्राइजेज- 3645.35 6.86 4,15,570.31
अदाणी पोर्ट्स -1585.00 10.25 3,42,382.02
अदाणी पावर -875 15.64 3,37,482.16
अदाणी एनर्जी -1222.05 8.84 1,36,318.78
अदाणी ग्रीन -2037.65 6.39 3,22,770.38
अदाणी टोटल -1,119.85 7.77 1,23,162.23
अदाणी विल्मर -363.35 3.51 47,873.66
अंबुजा सीमेंट -670.60 5.72 1,65,177.06
एसीसी- 2677.45 5.16 50,279.10
एनडीटीवी- 263.25 6.15 1,697.21
कुल पूंजीकरण- 19,42,713.44

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का नाम गौरवशाली इतिहास में अंकित है

मुदित अग्रवाल

मोदी जी ने चुनाव में अथाह मेहनत की है और उसी कारण इतने भयानक जातीय गोलबंदी के बावजूद भाजपा कांग्रेस से ढाई गुना आगे है। मोदी का चेहरा आज भी लोगों में सबसे अधिक मान्य है और भाजपा का मत प्रतिशत पूर्व की भाँति बरकरार रहा है।

जातिय भगदड़ को बहुत ही सटीक तरीक़े से अंजाम दिया गया और आज भी उस भगदड़ में शामिल लोग कांग्रेस के समर्थन को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं पर वह इस बात से खुश हैं कि इन्होंने मोदी जी को सबक़ सिखा दिया। वास्तविकता यह है कि यदि उम्मीदवारों के चयन में भाजपा संगठन ने थोड़ी भी मेहनत की होती तो आज फिर से भाजपा सबसे बड़ी पार्टी होने के बजाय पूर्ण बहुमत वाली पार्टी होती। उबाऊ, थकाऊ, ज़मीन से कटे, रिपीटेड उम्मीदवारों ने लोगों के असंतुष्टि को एक कारण दे दिया। बहुत से लोग जातीय गोलबंदी के कारण भाजपा के विरोध में पहले से थे लेकिन उनका जमीर किसी अन्य पार्टी को वोट देने से रोक रहा था। लेकिन उम्मीदवारों ने ऐसे लोगो को स्पष्ट मौक़ा दे दिया।

जातिगत माँगो के संबंध में विभिन्न जातियों के माँगों का ठेका छोटी छोटी जातीय आधार रखने वाली पार्टियों के पास चला गया है। भाजपा के अंदर संबंधित जाति के नेता अपने समाज के मुद्दों पर मौन रहते हैं। भाजपा को कांग्रेस से यह कला सीखनी पड़ेगी कि किस प्रकार से वह आपसी विरोधी जातियों के नेताओं को आराम से अलग अलग मुद्दों पर भौंकने देते हैं और वह एक साथ पार्टी में बने रहते हैं। जाति नाम का मेंटल डिसऑर्डर हमारे समाज में बहुत पुराना है। इसका स्थायी इलाज संगठन करे लेकिन जब तक वह इलाज पूर्ण नहीं होता तब तक इसका सिंपटोमैटिक ट्रीटमेंट यहीं है कि अपने नेताओं को भी भौकने दिया जाय।

कुछ और विषय जिस पर भाजपा के प्रवक्ताओं की न कोई ट्रेनिंग हुई और न ही उन्होंने उसे छुआ। वास्तविकता यह है पिछले दस साल में देश में प्राइवेट सेक्टर में अथाह ग्रोथ हुआ है। लोगों को उनके सऊर के अनुसार बहुत रोज़गार दिया गया है। भाजपा के प्रवक्ता इस बात को बोलने से इनकार करते रहे। हम सब के आँखों के सामने सबके जीवन स्तर में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। सबके शरीर में बिना फटे कपड़े दिखाई दे रहे हैं, भूख से होने वाली मौत इस देश से समाप्त हो चुकी है। कई करोड़ लोगों के सिर पर छत आ गई। करोड़ों लोगों ने शौच करने का तरीक़ा सीखा है। अधिकांश आबादी के पास अब दो जोड़ी से अधिक कपड़े, एक जोड़ी से अधिक जूते चप्पल हैं। लोगों को इलाज की सुविधा मिली है, इलाज न मिलने के कारण होने वाली मौतें बहुत कम हुई हैं। लेकिन

इसको ठीक से कोई बोलने वाला नहीं मिला। महंगाई पिछले एक दशक से सबसे कम दर से बढ़ी लिखने इसको बोलने में हर प्रवक्ता कतराते रहे।

ऐसे और कई कारण हैं जिस को मैं लिख सकता हूँ लेकिन फ़िलहाल मुझे ये कारण नज़र आ रहे हैं जिस कारण पार्टी कम से कम और तीस चालीस सीट लाने में नाकामयाब हुई है। मोदी जी ने दूसरे चरण के बाद जो मेहनत की है वह हमें यह सीख देता है कि चाहे आपकी उम्र कोई भी हो, चाहे आपकी अवस्था कोई भी हो लेकिन जब आपको व्यक्तिगत रूप से पता चल जाता है कि हमारी तरफ़ चीजें ठीक नहीं चल रहीं तो अथाह मेहनत और परिश्रम करके उसे ठीक करने के लिए जी जान लगा दिया जाता है।

गलती क्षेत्रीय नेताओं की उदासीनता, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और अहंकार की है न कि राष्ट्रीय नेता मोदी की। कार्यकर्ता की उपेक्षा किसी ने की है तो दोयम दर्जे के नेताओं ने की है न कि उस मोदी ने जो माताओं के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। यही मोदी भाजपा को वहां तक लाये जहां बहुमत से केवल थोड़ी सी सीट कम होना भी कार्यकर्ता को ठेस पहुंचा रहा है। मोदी की निष्कंटक सरकार बन रही है, इस बारे में कोई भ्रम न पालें।

पता नहीं क्या सोचकर ऐसे विचार आते हैं कि ₹श्रीराम बड़े न्यायप्रिय हैं, और राम से पहले तो इन्हें हनुमान जी ही रोक देंगे उद्दण्ड होने से।₹ आश्चर्य है कि 60 साल राममंदिर लटकाने वालों को श्रीराम नहीं रोकेंगे, पर धर्म के लिए न भूतो न भविष्यति कार्य करने वाले नरेन्द्र मोदी को हनुमान जी से रुकवाया जाएगा। बाकी रामलला ने इतनी विपरीत परिस्थितियों के उपरांत भी मोदी जी को ही विजय दिलाई है। जहाँ कहीं हार हुई है तो वह घर के अंदर बहुत छोटी छोटी गलतियों, अहंकारों, स्वार्थों के टकराने का दुष्परिणाम है, जिन्हें थोड़ी सी समझदारी से ही आराम से सुलझाया जा सकता है।

राष्ट्रजीवन में इससे भी ज्यादा नाजुक क्षण आए हैं, और यह तो विजय का ही समय है पराजय का नहीं। ऐसी विजय अच्छी है जिससे बिना हारे ही बहुत कुछ सीखा जा सके। नरेन्द्र मोदी ने अपना सर्वस्व एक कर अंतराष्ट्रीय शक्तियों द्वारा सोशल मीडिया में धन बहाने के बावजूद विपक्ष की देशविघातक योजनाओं के लुभावने वादों को विफल कर, चुनाव को एक ऐसी स्थिति तक खींच दिया जहाँ से हिन्दू वर्चस्व खत्म नहीं किया जा सकेगा। भाजपा विश्व की गिनी चुनी पार्टियों में से एक होगी जिसने शताब्दी संघर्षों वाले अपने वादे पूर्ण किए, 370 से लेकर राममंदिर जैसे अपने वादों को पूरा करने वाले बहुत ही कम राजनीतिक क्षण विश्व इतिहास में दर्ज होंगे। उनमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का नाम गौरवशाली इतिहास में अंकित है।

कभी थे अकेले हुए आज इतने
नहीं तब डरे तो भला अब डरेंगे
विरोधों के सागर में चट्टान है हम
जो टकराएंगे हमसे मौत अपनी मरेंगे
लिया हाथ में ध्वज कभी न झुकेगा
कदम बढ़ रहा है कभी न रूकेगा
न सूरज के सम्मुख अंधेरा टिकेगा
निडर है सभी हम अमर है सभी
के सर पर हमारे वरदहस्त करता
गगन में लहराता है भगवा हमारा

4-5 राज्यों में न भाजपा न कांग्रेस, क्षेत्रीय दल बने किंग या किंगमेकर, क्या भारत में भी 2 पार्टी सिस्टम होना चाहिए

140 करोड़ की आबादी वाले भारत में महज दो दलों वाली प्रणाली अपनाना संभव नहीं होगा। देश में जाति-भाषा और धर्म के आधार पर भले ही बंटवारा हो, मगर इसकी बहुलता ही इसकी जान है। इस देश में वोटरों के पास राष्ट्रीय पार्टियों के अलावा क्षेत्रीय पार्टियों का भी विकल्प है, जो लोकतंत्र की बड़ी ताकत है।

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव, 2024 में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दलों का एक बार फिर से प्रभाव बढ़ा है। ये क्षेत्रीय पार्टियां या तो सरकार बनाने की स्थिति में हैं या किंगमेकर की भूमिका में हैं। ऐसे में एक बार फिर से इस बहस ने जोर पकड़ लिया है कि क्या भारत में अमेरिका की तरह 2 पार्टी सिस्टम होना चाहिए। क्या मतदाताओं का मन दो दलीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है? आखिर वोटर्स क्या सोचते हैं? आइए-इस बारे में समझते हैं कि आखिर 2 पार्टी सिस्टम क्या है? क्या देश क्षेत्रीय दलों पर भरोसा ज्यादा जता रहा है? वोटर्स के मन में क्या चल रहा होता है?

पहली बार 1977 में 11 पार्टियों ने बनाई थी गठबंधन सरकार

1977 में पहली बार केंद्र में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 11 पार्टियों ने गठबंधन सरकार बनाई। इसके बाद चौधरी चरण सिंह ने 1979 में गठबंधन सरकार बनाई। फिर वीपी सिंह, चंद्रशेखर, एचडी देवगौड़ा ने गठबंधन सरकार बनाई।

देश की पहली अल्पमत नरसिम्हा राव सरकार थी

देश की पहली अल्पमत वाली सरकार नरसिम्हा राव की सरकार थी, जिन्होंने राजीव गांधी की हत्या के बाद जीत दर्ज की थी। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की पहली 13 दिन की सरकार बनी, जो गठबंधन आधारित थी।

संयुक्त मोर्चा सरकार भी गठबंधन की सरकार

संयुक्त मोर्चा सरकार 13 पार्टियों से मिलकर बनी थी। पहले इसके प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और फिर इंद्र कुमार गुजराल बने। इसके बाद वाजपेयी फिर 1998 में लौटे और उन्होंने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) की सरकार बनाई, जिसे जयललिता की अन्नाद्रमुक सरकार ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। 1999 से 2004 के बीच एनडीए ने सरकार बनाई, जो 20 सहयोगी दलों के समर्थन से बनी थी। उस वक्त विपक्ष में कांग्रेस ने 14 पार्टियों का युनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस (UPA) का गठबंधन बनाया था।

अभी इंडिया अलायंस 27 पार्टियों का गठबंधन

मौजूदा सियासत में कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन जहां 27 पार्टियों से मिलकर बना है, वहीं भाजपा की अगुवाई वाला एनडीए गठबंधन 38 पार्टियों से मिलकर बना है।

लोकसभा चुनाव में क्यों लगा बीजेपी को इतना बड़ा झटका, कहीं ये 5 वजह तो नहीं?

परिवहन विशेष न्यूज

अबकी बार-400 पार के नारे के साथ शुरू हुआ एनडीए का चुनावी अभियान नतीजों में बदलता हुआ नहीं दिख रहा है। अभी तक की मतगणना को देखें तो एनडीए को बहुमत मिल रहा है, लेकिन बीजेपी 272 के आंकड़े से भी पीछे है। वहीं, विपक्षी दलों ने जबरदस्त वापसी की है।

नई दिल्ली: 1 जून 2024 की शाम करीब 6:30 बजे एग्जिट पोल के नतीजे आने शुरू हुए। किसी को अंदाजा नहीं था कि एग्जिट पोल में बीजेपी और एनडीए को इतना भारी बहुमत मिलेगा। ज्यादातर एग्जिट पोल ने एनडीए को 350 से ऊपर सीटें दी। कई एग्जिट पोल के नतीजों में तो एनडीए को 400 का आंकड़ा छूते हुए बताया गया। ठीक इसी तरह तीन दिन बाद आए चुनाव नतीजों ने भी अब हर किसी को हैरान कर दिया है। अभी तक की मतगणना के आंकड़े देखें, तो बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में बीजेपी बुरी तरह पिछड़ रही है। वहीं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्ष के कई दलों ने जबरदस्त वापसी की है। आइए जानते हैं कि आखिर किन वजहों से बीजेपी उम्मीद के मुताबिक सीटें हासिल करने से चूक गई।

1- केवल मोदी मैजिक के सहारे रहना

पिछले दो महीनों में बीजेपी और एनडीए में उसके सहयोगी दलों का चुनाव प्रचार देखें, तो एक बात साफ तौर पर नजर आती है कि इन्होंने केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। चुनावी रैलियों और सभाओं में पार्टी के छोटे-बड़े सभी नेता स्थानीय मुद्दों से बचते हुए नजर आए। पूरा प्रचार केवल और केवल पीएम मोदी के करिश्मे पर टिका था। बीजेपी के प्रत्याशी और कार्यकर्ता भी जनता से कनेक्ट नहीं हो पाए, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। दूसरी तरफ, विपक्ष लगातार महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों के जरिए सरकार के प्रति नाराजगी को जोर-शोर से उठाता रहा।

2- बीजेपी के वोटर्स की नाराजगी

लोकसभा चुनाव के नतीजे इस बात के भी संकेत दे रहे हैं कि कई बड़े मुद्दों पर बीजेपी को अपने ही वोटर्स की नाराजगी झेलनी पड़ी। अग्निवीर और पेपर लीक जैसे मुद्दे साइलेंट तौर पर बीजेपी के खिलाफ काम करते रहे। वोटर्स के बीच सीधा मैसेज गया कि सेना में चार साल की नौकरी के बाद उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा? पेपर लीक के मुद्दे पर युवाओं की नाराजगी को समझने में बीजेपी ने चूक की। पुलिस भर्ती परीक्षा के मुद्दे पर यूपी के लखनऊ में हुआ भारी विरोध प्रदर्शन इसका गवाह है। पार्टी के नेता ये मान बैठे थे कि केवल नारेबाजी से वो अपने समर्थकों और वोटर्स को खुश कर सकते हैं।

3- महंगाई

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि महंगाई के मुद्दे ने इस चुनाव पर बहुत ही गहरा असर डाला। पेट्रोल-डीजल से लेकर खाने-पीने की चीजों पर लगातार बढ़ रही महंगाई ने सरकार के खिलाफ एक माहौल पैदा किया। विपक्ष इस मुद्दे के असर को शायद पहले ही भांप गया था, इसलिए उसने हर मंच से गैस सिलेंडर सहित रसोई का बजट बढ़ाने वाली दूसरी चीजों की महंगाई को मुद्दा बनाया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बढ़ती महंगाई के लिए आर्थिक नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कई बार प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला बोला। दूसरी तरफ, बीजेपी नेता और केंद्र सरकार के मंत्री महंगाई के मुद्दे पर केवल आश्वासन भरी बातें करते हुए नजर आए।

4- बेरोजगारी

2024 के इस लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी के मुद्दे ने एक बड़े फैक्टर के तौर पर काम किया। विपक्ष ने हर मंच पर सरकार को घेरते हुए बेरोजगारी के मुद्दे पर जवाब मांगा। यहां तक कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा कर दिया कि अगर उनकी सरकार केंद्र में बनती है, तो तुरंत 30 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। मंगलवार को घोषित चुनाव नतीजे साफ तौर पर संकेत दे रहे हैं कि राम मंदिर, सीएए लागू करने की घोषणा और यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दे भी बीजेपी को बेरोजगारी के खिलाफ बने माहौल के नुकसान से नहीं बचा पाए।

5- स्थानीय नाराजगी का नुकसान

बीजेपी को इस चुनाव में स्थानीय स्तर पर भी भारी नाराजगी झेलनी पड़ी। कई सीटों पर टिकट बंटवारे की नाराजगी मतदान की तारीख तक भी दूर नहीं हो पाई। कार्यकर्ताओं के अलावा सवर्ण मतदाताओं का विरोध भी कुछ सीटों पर देखने को मिला। कुल मिलाकर कहा जाए तो बीजेपी इस चुनाव में केवल उन मुद्दों के भरोसे रही, जो आम जनता से कोसों दूर थे।

भयंकर गर्मी से बचने का सिर्फ एक उपाय, आइए हम सब मिलकर अपने आस-पास छायादार पेड़ लगाएं : राष्ट्रवादी चिंतक राजेश खुराना

बरगद एक लगाइये, पीपल रोपें पाँच, घर - घर नीम लगाइये, यही पुरातन साँच : राष्ट्रवादी चिंतक राजेश खुराना
आओ पेड़ लगाये, साथ ही अपना और अपनो का वर्तमान और भविष्य तथा जीवन बचायें, प्रकृति को जीवंत बनाएं : राष्ट्रवादी चिंतक राजेश खुराना

आगरा। हर वर्ष हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, इसके तापमान का संतुलन बनाए रखने के लिए पृथ्वी का हरा-भरा होना अति आवश्यक है। हम चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, यदि तापमान/गर्मी इसी तरह बढ़ती रहेगी तो आने वाले समय में इसका भयंकर परिणाम होगा। वहीं, इस बार की प्रचंड गर्मी ने सारे रिकार्ड ध्वस्त कर दिये हैं। पता नहीं अभी पारा और कितना ऊपर जायेगा। आज हर शख़्स गर्मी से परेशान है, हर तरफ़ हाय हाय मची हुई है। आज लोगों को बहुत गर्मी लग रही है, लेकिन कब तक ऐसी कूलर का सहारा लेंगे, आज पूरे भारत में करोड़ पेड़ों की जरूरत है। तापमान कुछ ही समय में 40°C से 47°तक पहुंच जाता है। 56°C में इंसानों का जीवित रहना मुश्किल होगा और अभी गर्मी ने तो अपना तेवर दिखाना शुरू ही किया है। 45 से 49 डिग्री को 56° होने में देर नहीं लगेगी। अभी से आगामी वर्षो में खरतनाक गर्मी का क्या सितम होगा? ये एक कुदरत की चेतावनी हैं अभी से सतर्क हो जाइये और पौधे लगाने की शुरु कर दीजिए क्योंकि एक पौधे को बड़ा होने मे कम से कम 5 साल लग जाएगे। इसलिए अभी भी समय हैं जागिये, दूसरों या सरकार के भरोसे मत रहिये। अपने आस पास अधिक से अधिक पौधे लगाएं, वर्तमान और भविष्य को बचाएं। ये बात आगरा के सुप्रशिद्ध एवं लोकप्रिय वरिष्ठ समाजसेवी, राष्ट्रवादी सामाजिक चिंतक राजेश खुराना व उनका परिवार भी ख़ूब समझता हैं।

हर साल बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी को देखते हुये राष्ट्रवादी चिंतक राजेश खुराना ने सभी से हाथ जोड़कर विनम्र विनती करते हुये कहा कि हम अपने मन में यह विचार रखें कि पर्यावरण को बचाना है, सुरक्षित रखना है, तो आइए हम सब मिलकर अपने आस - पास अधिक से अधिक छायादार पेड़ लगाएं। वर्तमान और भविष्य बचाएं, साथ ही अपना और अपनो का जीवन बचायें तथा प्रकृति को जीवंत बनायें। आओ ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए। यकीन जानिए अगर, हम 150 करोड़ लोग यदि एक - एक पेड़ लगा दे और उसकी देखभाल करे तो मजाल है इतनी गर्मी परेशान करे, चलो शुरुआत करे। क्योंकि इस प्रचंड गर्मी से निजात पाने का अब बस एक ही परमानेंट तरीका हैं कि अपने आस - पास ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए। अभी भी समय है, हर आदमी पेड़ लगाए और उसकी देखभाल करे, अगर पेड़ पौधे नही लगाए गए तो आने वाला समय इससे भी भयावह होगा। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 22 करोड़ से ज्यादा हैं, अगर आज सिर्फ एक पेड़ लगाता है, तो सीधे 22 करोड़ पेड़ उगेंगे और अगली गर्मियों

में तापमान 30 डिग्री होगा और बारिश भी अधिक होंगी। इसलिए आज थोड़ा अगली पीढ़ी के बारे में सोचो और एक पेड़ लगाएं। जैसे लोग अच्छे भविष्य कि सोचकर अपने बच्चों के लिए बीमा करते हैं, इसी तरह भविष्य में बच्चों को अच्छा पर्यावरण मिलें। इसके लिए पेड़ लगाना चाहिए और पौधों को बचाना चाहिए। पेड़ पौधे हैं, तो पृथ्वी पर जीवन है। जब पृथ्वी पर जीवन ही नहीं रहेगा तो इतनी टेक्नोलॉजी बनाकर क्या करोगे इंसान? इसलिए पेड़ों को ना काटा जाए तथा ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाया जाए ताकि पर्यावरण और जीवन दोनों को बचाया जा सके। सोचिये 45° डिग्री टेंपरेचर की गर्मी में ऐसी कूलर पंखा बिल्कुल काम नही कर रहैं है और जिनके पास कुछ नहीं है वह किस तरह कैसे रहते होंगे? पेड़ पौधे एकदम बड़े नहीं होते उनको बड़े होने में कमसे कम 5 साल का लगता है, इसलिए हमें पेड़ का उचित स्थान का चयन करके अच्छे छायादार व फलदार वृक्ष लगाने चाहिए। पिछले 68 सालों में पीपल, बरगद और नीम के पेडों को लगाने का चलन कम हुआ हैं। जबकि पीपल कार्बन डाई ऑक्साइड का 100% एबजॉर्बर है, बरगद 80% और नीम 75 % हैं, लेकिन इसके बदले लोगों ने विदेशी यूकेलिप्टस को लगाना शुरू कर दिया, जो जमीन को जल विहीन कर देता है। आज हर जगह यूकेलिप्टस, गुलमोहर और अन्य सजावटी पेड़ो ने ले ली है। अब जब वायुमण्डल में रिफ्रेशर ही नहीं रहेगा तो गर्मी तो बढ़ेगी ही, और जब गर्मी बढ़ेगी तो जल भाप बनकर उड़ेगा ही इसलिए हर 500 मीटर की दूरी पर एक पीपल का पेड़ लगायें, तो आने वाले कुछ साल भर बाद प्रदूषण मुक्त भारत होगा।पीपल के पत्ते का फलक अधिक और डंठल पतला होता है, जिसकी वजह शांत मौसम में भी पत्ते हिलते रहते हैं और स्वच्छ ऑक्सीजन देते रहते हैं। वैसे भी पीपल को वृक्षों का राजा कहते है। इन जीवनदायी पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा लगाने के लिए समाज में जागरूकता बढ़ायें, बाग बगीचे बनाइये, पेड़ पौधे लगाइये, जैसे मनुष्य को हवा के साथ पानी की जरूरत है, वैसे ही पेड़ पौधों को भी हवा के साथ पानी की जरूरत है।बरगद एक लगाइये, पीपल रोपें पाँच, घर - घर नीम लगाइये, यही पुरातन साँच। यही पुरातन साँच, आज सब मान रहे हैं। भाग जाय प्रदूषण सभी अब जान रहे हैं। विश्वताप मिट जाये, होय हर जन मन गदगद, धरती पर त्रिदेव हैं, नीम पीपल और बरगद। इसलिए कम से कम एक व्यक्ति ने हर वर्ष अपने जन्मदिन पर एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। तभी हम इस पृथ्वी को बचा पाएंगे और धरती का तापमान हरियाली से ही संतुलित रहेगा।

श्री खुराना ने आगे कहा कि जब कोरोना आया तब सभी बड़े उत्सुक थे की अब धरती माँ का श्रृंगार हरियाली से कर देंगे लेकिन जैसे ही सामान्य हुआ सभी भूल गए। हम अगर एक पेड़ लगाए या जो पेड़ गवर्नमेंट ने सडक के किनारे लगाए है। ऑफिस जाते समय या दैनिक कार्य से निकलते हुए एक बोतल पानी साथ लेकर निकले और प्रतिदिन प्रति व्यक्ति सिर्फ एक पेड़ को पानी दे तो पेड़ पौधो की संख्या बढ़ने लगेगी। क्योंकि सरकार द्वारा लगाए गए पेड़ पौधे देखभाल और पानी की कमी मे सुख जाते है और करोडों.रुपये बर्बाद हो जाते हैं। जरा सोचिये जैसे गर्मी के कारण अपने अपने घरों के कूलर में आजकल लोग हवा को ठंडा रखने के लिए दिन में 4 बार पानी डालते है। वैसे ही यदि पेड़ में 1बार भी पानी डालते रहे तो पेड़ पौधे हरे भरे लहलहाते दिखएंगे और तापमान सामान्य रूप में आ जायेगा। अगर हम सभी व्यक्तिगत तौर पर आगे आएँ और सरकार द्वारा लगाएं गए पेड़ पौधों की सुरक्षा हमें सभी राष्ट्रहित में अपना नैतिक कर्तव्य समझते हुए पहल करते हुए ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए और सरकार का सहयोग करना चाहिए। हमें अपने जीवन में पेड़-पोधौ के महत्व को समझना चाहिए। जब पेड़ भी नहीं रहेंगे तो गर्मी तो पड़ेगी ही और इस भयंकर गर्मी से बचने के लिए और परमानेंट सॉल्यूशन के लिए एक ही रास्ता है अपने आस पास ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं। अबकी बार बढ़ती गर्मी को रोकने के लिए और पर्यावरण को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा वृक्ष रोपन करें। आओ मिलकर प्रकृति बचाएं, छायादार पेड़ लगाएं और गर्मी भगाएं। हमारी ये छोटी सी पहल आने वाले भविष्य और आने वाली पीढ़ी के लिए वरदान साबित होंगी।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023